

नेतृत्व और रणनीतिक कौशल को सशक्त बनाने के लिए छह हाई-इम्पैक्ट मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स लॉन्च किए

रायपुर, संवाददाता

भारतीय प्रबंधन संस्थान रायपुर, जो व्यावसायिक नेताओं को तैयार करने के लिए एक प्रमुख संस्थान के रूप में प्रसिद्ध है, ने अक्टूबर और नवंबर 2025 में आयोजित किए जाने वाले छह हाई-इम्पैक्ट मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स की घोषणा की है। ये अल्पकालिक कार्यक्रम वरिष्ठ कार्यकारी, मध्य-स्तरीय प्रबंधक, कार्यात्मक नेता और निर्णय निर्माता के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, जिनका उद्देश्य प्रबंधकीय क्षमता, रणनीतिक सोच और नेतृत्व कौशल को निखारना है।

21 अक्टूबर से 24 नवंबर 2025 तक चलने वाले ये कार्यक्रम वित्त, मानव संसाधन, रणनीतिक प्रबंधन, संगठनात्मक व्यवहार और कॉर्पोरेट संचार जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को कवर करेंगे। अक्टूबर में फ़र्नेशियल रिस्क मैनेजमेंट, डॉ. प्रणिथ कुमार रॉय द्वारा संचालित, और ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स का विश्लेषण, डॉ. दामिनी सैनी द्वारा संचालित, पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, जो प्रतिभागियों को वित्त, जोखिम मूल्यांकन और संगठनात्मक व्यवहार में विशेषज्ञता प्रदान करेंगे। नवंबर में कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन, डॉ. अर्चना प्रसाद और डॉ. मृणाल



चवड़ा द्वारा संचालित, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, डॉ. सत्यसिबा दास द्वारा संचालित, प्रैक्टाइजिंग फॉर बिजनेस ग्रोथ, डॉ. संदीप एस. द्वारा संचालित, और एचआर एनालिटिक्स, डॉ. ऋतु गुप्ता द्वारा संचालित, जैसे कार्यक्रम नेतृत्व, बातचीत, संचार, रणनीतिक निर्णय और व्यवसाय विस्तार क्षमताओं को बढ़ाएंगे।

आईआईएम रायपुर के निदेशक-इन-चार्ज प्रोफेसर संजीव प्रसाद ने इन कार्यक्रमों के पीछे की रणनीति को रेखांकित करते हुए कहा, हमारे मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स उन बदलती चुनौतियों को संबोधित करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, जिनका

सामना पेशेवर विभिन्न उद्योगों में कर रहे हैं। ये कार्यक्रम शोध-आधारित अंतर्दृष्टि और अनुभवात्मक सीखने को जोड़ते हैं, प्रतिभागियों को व्यावहारिक उपकरण, रूपरेखाएँ और मानसिकता प्रदान करते हैं ताकि वे नवाचार को आगे बढ़ा सकें, निर्णय लेने को बेहतर बना सकें और स्थायी व्यावसायिक वृद्धि प्राप्त कर सकें। हमारा उद्देश्य केवल प्रबंधकों को तैयार करना नहीं है, बल्कि ऐसे नेताओं को तैयार करना है जो सार्वजनिक नीति, कॉर्पोरेट रणनीति और सामाजिक नवाचार में परिवर्तनकर्ता बन सकें।

ये कार्यक्रम अवधारणात्मक रूपरेखा, केस-स्टडी

आधारित शिक्षा, व्यावहारिक अभ्यास और वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों को एकीकृत करते हैं, जिससे प्रतिभागी तुरंत अपने पेशेवर परिवेश में सीख को लागू कर सकें और विभिन्न क्षेत्रों के साथ-साथ सहकर्मियों-से-सीखने और नेटवर्किंग के अवसरों का लाभ उठा सकें। फ़र्नेशियल रिस्क मैनेजमेंट 21 से 23 अक्टूबर, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन 1 से 4 नवंबर, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग 16 से 18 नवंबर, प्रैक्टाइजिंग फॉर बिजनेस ग्रोथ 21 से 23 नवंबर, और एचआर एनालिटिक्स एवं ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स का विश्लेषण 22 से 24 नवंबर को आयोजित किए जाएंगे।

ये पहल आईआईएम रायपुर की उस प्रतिबद्धता को दोबारा प्रमाणित करती हैं, जिसके तहत यह पेशेवरों को ज्ञान, नेतृत्व कौशल और रणनीतिक दृष्टिकोण से लैस करने के लिए काम करता है, ताकि वे आधुनिक व्यावसायिक और संगठनात्मक परिवेश की जटिलताओं को सहजता से नेविगेट कर सकें। सिद्धांत और व्यावहारिक अंतर्दृष्टि के संयोजन के माध्यम से ये कार्यक्रम प्रतिभागियों को ऐसे अग्रणी नेता बनने के लिए तैयार करते हैं, जो नवाचार, सूचित निर्णय और स्थायी विकास को बढ़ावा देने में सक्षम हों।

कांग्रेस ने नक्सलवाद खत्म नहीं किया, केवल राजनीति की है : विधायक सोनी

रायपुर, । नक्सली संरेंडर पर कांग्रेस के तंज कसे जाने पर भाजपा विधायक सुनील सोनी ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने नक्सलवाद खत्म नहीं किया, केवल राजनीति की है। आज नक्सली या तो ढेर हो गए या फिर आत्मसमर्पण कर रहे हैं। जिसे लोग असंभव कहते थे, नरेंद्र मोदी, अमित शाह और हमारी सरकार ने इसे संभव करके दिखा रही हैं। वहीं बाधिन की मौत पर नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरण दास महंत के राज्यपाल को पत्र लिखे जाने पर सुनील सोनी ने कहा कि मौत पर राजनीति करना कांग्रेस का काम है। पत्र लिखना कांग्रेसियों की आदत है, यह केवल महंत जी की बात नहीं है। उन्होंने कहा कि



भूपेश बघेल भी दर्जनों पत्र प्रधानमंत्री को लिखा चुके हैं। यह केवल पत्र लिखकर औपचारिकता पूरी करते हैं। कोई तथ्य और सबूत नहीं देते। भारतीय जनता पार्टी की सरकार सजग है। अगर कहीं लेगेगा गड़बड़ हुआ है, तो उसकी जांच की जाएगी। भाजपा की सरकार जांच से नहीं बचती।

विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने ठाठापुर में की पूजा

रायपुर, । राजधानी रायपुर के ग्राम ठाठापुर में बीते नरक चतुर्दशी के पावन अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने अपने कुलदेवता की पूजा-अर्चना कर आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर ग्रामवासियों ने अध्यक्ष का स्नेहपूर्ण स्वागत किया, जिससे वे अभिभूत हुए। डॉ. रमन सिंह ने पूजा-अर्चना के दौरान ग्रामवासियों के साथ बातचीत की और उन्हें दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएँ दी। उन्होंने कहा कि यह पर्व जीवन में उजाला, सुख और समृद्धि लाने वाला है। नरक चतुर्दशी को बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है और इसे श्रद्धा एवं उल्लास के साथ मनाया चाहिए।

अध्यक्ष ने ग्रामवासियों से अनुरोध किया कि वे इस पर्व को सौहार्द और भाईचारे के साथ मनाएं। उन्होंने बताया कि इस अवसर पर उन्होंने अपने कुलदेवता का आशीर्वाद लिया ताकि पूरे परिवार और ग्रामवासियों का जीवन खुशियों और समृद्धि से भरा रहे। इस अवसर पर डॉ. रमन सिंह ने सभी ग्रामवासियों को नए विधानसभा भवन के लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल होने के



लिए भी सादर आमंत्रित किया। उन्होंने कहा कि नए भवन का लोकार्पण छत्तीसगढ़ की लोकतांत्रिक प्रक्रिया और विकास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। स्थानीय लोगों ने विधानसभा अध्यक्ष के आगमन और स्नेहपूर्ण व्यवहार की सराहना की। उनका कहना है कि अध्यक्ष का यह दौरा ग्रामवासियों के लिए प्रेरणा और उत्साह का स्रोत रहा। इसके साथ ही ग्रामीणों ने उन्हें अपने क्षेत्र की जरूरतों और विकास कार्यों के बारे में भी

जानकारी दी। डॉ. रमन सिंह के इस दौरे ने नरक चतुर्दशी के अवसर को और भी खास बना दिया। उनके साथ ग्रामवासियों के साझा उत्साह ने सांस्कृतिक और सामाजिक सौहार्द का संदेश दिया। इस अवसर पर अध्यक्ष ने सभी से अपील की कि दीपावली के पर्व को पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक जिम्मेदारी के साथ मनाएं, ताकि आने वाली पीढ़ियाँ भी इस सांस्कृतिक धरोहर का आनंद ले सकें।

प्रधानमंत्री उज्जवला योजनांतर्गत दिए जाएंगे 2.23 लाख से अधिक नवीन घरेलू एलपीजी कनेक्शन

प्रधानमंत्री उज्जवला योजना अंतर्गत एलपीजी कनेक्शन हेतु अब लिए जाएंगे नवीन आवेदन

रायपुर, (संवाददाता)।

भारत सरकार, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री उज्जवला योजना अंतर्गत 10.33 करोड़ से अधिक आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं घरेलू एलपीजी कनेक्शन देने के उपांगत एक बार फिर दीपावली के पूर्व लोगों को उपहार देते हुए पीएमयूवाय अंतर्गत 25 लाख नवीन उज्जवला गैस कनेक्शन प्रदान करने हेतु प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। छत्तीसगढ़ में 2 लाख 23 हजार नवीन घरेलू एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने हेतु लक्ष्य प्रदान किया गया है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने इस योजना के तहत नवीन कनेक्शन दिए जाने पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के प्रति अभार व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री श्री



साय के निर्देशानुसार नवीन उज्जवला गैस कनेक्शन के लिए छत्तीसगढ़ शासन के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं।

हितग्राहियों को 15 दिनों में दिए जाएंगे नवीन कनेक्शन विभाग द्वारा जारी विस्तृत दिशा-निर्देश अनुसार सभी जिलों में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला उज्जवला समिति का गठन किया जाएगा। इस समिति द्वारा जिले में

प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के क्रियान्वयन एवं प्राप्त आवेदनों की समय-सीमा में निराकरण हेतु नियमित मॉनिटरिंग की जाएगी। योजनांतर्गत पात्र परिवारों ने नवीन गैस कनेक्शन हेतु आगामी 07 दिनों में आवेदन पत्र प्राप्त किए जाएंगे। जिले की गैस एजेंसियों द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों का परीक्षण एवं सत्यापन कराकर 15 दिनों में नवीन गैस कनेक्शन जारी करने की कार्यवाही की जाएगी।

नियद नेल्ला नार योजना अंतर्गत

हितग्राहियों को दी जाएगी प्राथमिकता

नियद नेल्ला नार योजना अंतर्गत आने वाले बीजापुर, सुकमा, नारायणपुर, कांगेर, दत्तेवाड़ा जिलों में सर्वप्रथम हितग्राहियों को चिन्हांकित कर इन ग्रामों को विशेष प्राथमिकता देते हुए शत-प्रतिशत चिन्हांकित हितग्राहियों को उज्जवला गैस योजना के कनेक्शन दिए जाएंगे। पात्र हितग्राहियों को योजना का लाभ दिलाने जाने हेतु ऑयल कंपनियों के साथ समन्वय करते हुए सुगम नेटवर्क कनेक्टिविटी वाले क्षेत्रों का चयन कर विशेष शिविर आयोजित किये जाएंगे। योजनांतर्गत गैस कनेक्शन प्राप्ति हेतु शेष सभी 34 हजार 425 परिवारों के आवेदन चिन्हांकित ग्रामों में विशेष शिविर आयोजित कर लिए जाएंगे। दूरस्थ एवं दुर्गम क्षेत्रों से प्राप्त आवेदनों के ई-केवाईसी के लिये कनेक्टिविटी वाले क्षेत्रों का चयन कर विशेष शिविर द्वारा उन्हें लाभावित किया जायेगा।

फॉर्च्यूनर कार को बीच सड़क में खड़ी कर काटा केक मनाया बर्थडे, 4 युवक गिरफ्तार

दुर्ग, संवाददाता।

जिले के भिलाई में कुछ निगरानी बंदमाशों ने बीच सड़क पर बर्थडे सेलिब्रेट किया। बंदमाशों ने सड़क पर फॉर्च्यूनर कार खड़ी कर तेज म्यूजिक बजाया, 'बॉस' लिखा हुआ केक काटा, फिर जमकर आतिशबाजी की। बंदमाशों ने सड़क पर बर्थडे सेलिब्रेशन का वीडियो भी बनाया, जिसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। मामला दुर्ग के वैशाली नगर थाना क्षेत्र का है। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। घटना 13 अक्टूबर की करीब 12.30 बजे की है। सफेद रंग की फॉर्च्यूनर में सवार युवक - शुभम यादव, नीरज नेपाली, सत्यम यादव, जितेश यादव और रवि यादव वैशाली नगर क्षेत्र के कैम्प-1 पहुंचे। यहां इन्होंने सड़क के बीचो-बीच गाड़ी



खड़ी कर दी, जिससे रोड ब्लॉक हो गया। इसके बाद उन्होंने म्यूजिक सिस्टम ऑन किया और तेज आवाज में गाने बजाते हुए केक काटना शुरू किया। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि केक पर 'बॉस' लिखा हुआ था और सभी युवक खुलेआम सड़क पर मस्ती कर रहे थे। यह वीडियो वायरल होते ही पुलिस हरकत में आई। पुलिस के मुताबिक, शुभम यादव का बर्थडे था। चारों निगरानी बंदमाश है। कार किसकी है ये पता

लागाया जा रहा है। वीडियो के वायरल होते ही दुर्ग पुलिस ने इसे गंभीरता से लिया। थाना वैशाली नगर में मामला दर्ज किया गया। आरोपियों पर धारा 126(2), 190 और 3(5) भा.द.वि. के अंतर्गत केस दर्ज किया गया। इसके बाद पुलिस ने तुरंत दबिश देकर चार मुख्य आरोपियों शुभम यादव (32 वर्ष), सोहन मेथ्राम (35 वर्ष), रवि प्रसाद (26 वर्ष), नीरज कुमार सिंह (28 वर्ष) को गिरफ्तार कर लिया।

मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने बुजुर्गों संग मनाई दीवाली

रायपुर, (आरएनएस)। दीपावली के अवसर पर महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने माना रायपुर स्थित वृद्धाश्रम पहुंचकर वहाँ निवासरत वरिष्ठ नागरिकों के साथ दीवाली पर्व की खुशियाँ साझा कीं उन्होंने स्वयं दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की और बुजुर्गों को मिठाई, नए वस्त्र एवं उपहार प्रदान किए। वृद्धजनों के बीच बैठकर उन्होंने आत्मीय संवाद किया और उनके स्वास्थ्य तथा आवश्यकताओं की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि हमारे ये वरिष्ठ नागरिक हमारे समाज की अमूल्य धरोहर हैं। इनके अनुभव और आशीर्वाद से ही समाज की नींव मजबूत होती है। शासन का प्रयास है कि वृद्धजन सम्मानपूर्वक और आत्मसम्मान के साथ जीवन व्यतीत करें। कार्यक्रम के दौरान वृद्धाश्रम परिसर को दीपों और रंगोलियों से सजाया गया था। समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों ने मिलकर बुजुर्गों के साथ दीप जलाए। मंत्री राजवाड़े ने वृद्धाश्रम में उपलब्ध सुविधाओं का निरीक्षण करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि बुजुर्गों की देखभाल में किसी प्रकार की



कमी न रहे। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार वृद्धजनों के कल्याण हेतु वृद्धजन सेवा योजना, पेंशन सुविधा, स्वास्थ्य जांच शिविर, मानसिक-सामाजिक परामर्श केंद्र

जैसी योजनाओं का प्रभावी संचालन कर रही है। राजवाड़े ने कहा कि दीवाली केवल दीपों का पर्व नहीं, बल्कि संवेदनाओं को साझा करने का अवसर है। उन्होंने युवाओं से भी

अपील की कि वे इस पावन पर्व पर अपने आसपास के बुजुर्गों से मिलें, उनका आशीर्वाद लें और उन्हें अपनत्व का अहसास कराएँ।

ग्राम बुचीभरदा में 23 अक्टूबर को मातर महोत्सव का भव्य आयोजन



रायपुर – राजनांदागांव। ग्राम पंचायत आरला के आश्रित ग्राम बुची भरदा (सुरगी) में 23 अक्टूबर को मातर महोत्सव का भव्य आयोजन किया जा रहा है। ग्राम की सरपंच श्रीमती साधना राहुल साहू ने जानकारी देते हुए बताया कि कार्यक्रम का आयोजन दोपहर 12 बजे से शाम 6 बजे तक खेलकूद प्रतियोगिताओं के साथ किया जाएगा,

वहीं रात्रि में सांस्कृतिक कार्यक्रम के अंतर्गत मया के डोरी (ग्राम कांचरी, संगीत नगरी खैरागढ़) के कलाकार अपनी शानदार प्रस्तुति देंगे। सरपंच श्रीमती साधना राहुल साहू ने समस्त क्षेत्रवासियों से अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर कार्यक्रम का लाभ लेने एवं इस सांस्कृतिक उत्सव को सफ़्त बनाने की अपील की है।

सीजीएमएससी ने की 7 दवाएं ब्लैक लिस्टेड, 4 फर्मों को किया 3 साल के लिए प्रतिबंधित

7 दवाओं में 4 प्रकार की टैबलेट, दो इंजेक्शन व एक शैपो

रायपुर, संवाददाता।

छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेस कॉर्पोरेशन सीजीएमएससी ने 2023 में 7 प्रकार की दवाएं ब्लैक लिस्टेड कीं। 7 प्रकार की दवाओं में 4 प्रकार की टैबलेट, दो इंजेक्शन व एक शैपो है। 2025 में 4 फर्मों को बाहर का रास्ता दिखाया गया है। इनमें रीएजेंट की सप्लाई करने वाली मोक्षित कॉर्पोरेशन व इससे जुड़ी फर्म शामिल हैं। सीजीएमएससी ने फरवरी में 7 बड़ी कार्रवाई की थी। इसमें रीएजेंट सप्लाई करने वाले दुर्ग के मोक्षित कॉर्पोरेशन व उससे जुड़े दो अन्य फर्म और डीकेएस अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट आधा-अधूरा बनाने वाले फर्म शामिल है। चारों को 3-3 साल के लिए ब्लैक लिस्टेड किया गया है।



वहीं, खून पतला करने वाले इंजेक्शन हिपेरिन बनाने वाली वडोदरा की फर्मास्युटिकल कंपनी के अलावा इंजेक्शन को ओके रिपोर्ट देने वाली दो लैब के साथ रेट कट्रिक्ट खत्म किया गया है। 660 करोड़ के रीएजेंट व मेडिकल उपकरण घोटाले में दवा कॉर्पोरेशन के बड़े अधिकारियों की भी मिलीभगत होने की आशंका है, जिनके खिलाफ कार्रवाई होनी बाकी है। तत्कालीन हेल्थ डायरेक्टर व सीजीएमएससी के एमडी के खिलाफकोई कार्रवाई नहीं की गई है। विधानसभा में दी गई

जानकारी के अनुसार, 28 करोड़ के रीएजेंट खराब हो चुके हैं। यही नहीं, मोक्षित द्वारा सप्लाई ब्लड जांचने वाली मशीन भी बंद है, क्योंकि इसे लॉक कर दिया गया है। ताकि मोक्षित से ही रीएजेंट लिया जा सके। मोक्षित कॉर्पोरेशन के खिलाफ शिकायत 2022 में हुई थी, लेकिन मामला दबा दिया गया था।

पोर्टल सिस्टम से रियल टाइम जानकारी

सीजीएमएससी के कामों में पारदर्शिता लाने के लिए डीपीडीएमआईएस यानी ड्रग प्रोक्योरमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट इंफ़ॉर्मेशन सिस्टम पोर्टल को अब आम लोगों के लिए खोल दिया है। इस पोर्टल के माध्यम से प्रदेश के सभी स्वास्थ्य संस्थानों जैसे मेडिकल कॉलेज,

जिला अस्पताल, सीएचसी व पीएचसी में दवा, चिकित्सीय उपकरणों की आपूर्ति, वितरण, स्टॉक की स्थिति और यहां तक कि निर्माणाधीन अस्पताल भवनों की प्रगति को भी रियल-टाइम में देखा जा सकता है।

पोर्टल पर सभी निविदाएं, स्वीकृत आपूर्तिकर्ता और अनुबंध मूल्य सूची सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हैं। दवाओं की डिस्लीवरी, स्टॉक की वर्तमान स्थिति और लॉबिंग मांग की जानकारी दिन-प्रतिदिन अपडेट होती है। दवा परिवहन में लगे वाहनों की लाइव लोकेशन और उनके रुट की जानकारी भी नागरिक देख सकते हैं। निर्माणाधीन मेडिकल संस्थानों की प्रगति, बजट और योजनागत विवरण अब जनता की नज़रों में रहेगी।

फर्म ब्लैक लिस्टेड कब से कब तक कारण

सभी कंपनियों के प्रोडक्ट को 11 जुलाई 2023 से 11 जुलाई 2026 तक ब्लैक लिस्टेड किया गया है। इनमें मोक्षित कॉर्पोरेशन दुर्ग 4 फरवरी 25 से 3 फरवरी 28 तक भ्रष्टाचार व आपराधिक गतिविधियां

रेकॉर्ड एंड मेडिकेयर पंचकुला 5 फरवरी 25 से 4 फरवरी 28 तक भ्रष्टाचार व आपराधिक गतिविधियां

श्री शारदा इंडस्ट्रीज तर्रा 5 फरवरी 25 से 4 फरवरी 28 तक भ्रष्टाचार व आपराधिक गतिविधियां

मेडिलोब मेडिकल शंकरनगर 6 फरवरी 25 से 5 फरवरी 28 तक ऑक्सीजन प्लांट अधूरा व मटेनेंस नहीं करना

ये प्रोडक्ट ब्लैक लिस्टेड हिपेरिन इंजेक्शन बनाने वाली वडोदरा की डिवाइन लेबोरेटरी इंजेक्शन को ओके रिपोर्ट देने वाली इडमा लेबोरेटरी लिमिटेड

पंचकुला

लैब सेटिएट रिसर्च एंड अंटेक प्राइवेट लिमिटेड बरवाला पंचकुला

लिथियम कार्बोनेट 300 एमजी टेबलेट, जी लेबोरेटरी पोंटा साहेब हिमाचल प्रदेश।

एनालाप्रिल मैलेट 2.5 टेबलेट, डॉ. रेड्डी लेबोरेटरी हैदराबाद तेलंगाना।

मैग्नीशियम सल्फेट इंजेक्शन, भारत पैरेंटेरियल वडोदरा गुजरात।

क्लोरोफेनिराइमाइन 10 एमजी इंजेक्शन अल्लम लेबोरेटरी इंदौर मध्य।

केटोकोनाजोल 2 फीसदी शैपो, ग्लेनमार्क फर्मास्यूटिकल अंधेरी मुंबई।

क्लोपिडोग्रेल टेबलेट, रिवरा फार्मूलेशन हरिद्वार उत्तराखंड।

एसिटिल सैलिसिक एसिड 150 टेबलेट, यूनिक्वोर इंडिया नोयडा यूपी के साथ रेट कट्रिक्ट खत्म कर दिया गया है।



रायपुर। दीपावली और छठ जैसे बड़े त्योहारों पर रायपुर स्टेशन में यात्रियों की भीड़ बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति में प्लेटफार्म नंबर 5 की चौड़ाई कम होने के कारण रेलवे प्रशासन ने भीड़ बढ़ने की स्थिति में तीन एक्सप्रेस ट्रेनों को प्लेटफार्म नंबर 5 के स्थान पर 7 नंबर से चलने का निर्णय लिया है। यात्रियों से अनुरोध है कि वह सीधे प्लेटफार्म नंबर 7 पर पहुंचाएं। दुर्ग-पटना साउथ बिहार एक्सप्रेस और दुर्ग-छपरा सारनाथ एक्सप्रेस 22 से 27 अक्टूबर एवं गोंदिया-बरौनी एक्सप्रेस 23 अक्टूबर से प्लेटफार्म 07 से खाना होंगी।

मैसेज द्वारा उनके फोन नंबर पर भेजा गया है। लगातार रायपुर स्टेशन पर उद्घोषणा के माध्यम से भी यात्रियों को अवगत कराया जा रहा है। साथ ही कुलियों, सफाई कर्मियों आदि संचालकों को भी इस हेतु जागरूक किया गया है कि वह सीधे इन यात्रियों को प्लेटफार्म नंबर 7 पर पहुंचाएं। दुर्ग-पटना साउथ बिहार एक्सप्रेस और दुर्ग-छपरा सारनाथ एक्सप्रेस 22 से 27 अक्टूबर एवं गोंदिया-बरौनी एक्सप्रेस 23 अक्टूबर से प्लेटफार्म 07 से खाना होंगी।

नगर निगम रायपुर द्वारा 20 और 21 अक्टूबर को लगभग 52 मार्गों की मैकेनाइज्ड स्वीपिंग मशीन से 7 स्वीपिंग वाहन लगाकर दीपावली का कचरा साफ करने विशेष रात्रिकालीन सफाई



रायपुर – दीपावली पर्व में भारी मात्रा में निकलने वाले कचरे को साफ करने के उद्देश्य से रायपुर नगर पालिक निगम द्वारा महापौर श्रीमती मीनल चैबे, स्वास्थ्य विभाग अध्यक्ष श्रीमती गायत्री सुनील चंद्राकर, आयुक्त श्री विश्वदीप के निर्देश पर राजधानी शहर रायपुर नगर पालिक निगम क्षेत्र में सिविल लाईन, पंचशील नगर सहित लगभग 52 मार्गों में विगत दिनांक 20 और 21 अक्टूबर की रात्रि को विशेष रात्रिकालीन सफाई अभियान मैकेनाइज्ड स्वीपिंग मशीन से सात रोड स्वीपिंग वाहन

लगाकर लगभग 52 मार्गों में दीपावली पर्व के दौरान जनहित में जनस्वास्थ्य सुरक्षा की दृष्टि से स्वच्छता कायम की गयी है। जिससे दीपावली पर्व के दौरान मुख्य मार्गों में फटाकों का कचरा सहित अन्य सामग्रियों, पैपर आदि के कचरे के ढेर ना दिखें और इस विशेष रात्रिकालीन मैकेनाइज्ड स्वीपिंग अभियान के माध्यम से राजधानी शहर के रहवासियों को दीपावली पर्व के दौरान त्वरित राहत मिले और दीपावली पर्व के दौरान राजधानी शहर क्षेत्र के मार्गों में स्वच्छ वातावरण कायम रह सके।

राज्य में जनगणना के लिए नगरीय क्षेत्र में प्री टेस्ट जनगणना पूर्व परीक्षण हेतु चयन

भारत सरकार गृह मंत्रालय जनगणना कार्य निदेशालय के आदेशानुसार रायपुर नगर पालिक निगम जोन

क्रमांक 10 के डॉ राजेन्द्र प्रसाद वार्ड 52 का छत्तीसगढ़ 0

संवाददाता। निगम आयुक्त श्री विश्वदीप के निर्देश पर जोन 10 राजस्व विभाग नगर निवेश विभाग की टीम द्वारा वार्ड क्रमांक 52 के सभी लगभग 8000 जनगणना भवनों में भवन संख्या डालने और भवनों को सूचीबद्ध करने का कार्य निरन्तर प्रगति पर, अब तक लगभग 2500 भवनों में भवन संख्या डाली जा चुकी, जनगणना निदेशालय के अधिकारी श्री हरीन्द्र सिंह ने किया कार्य का प्रत्यक्ष निरीक्षण 0

रायपुर - भारत सरकार गृह मंत्रालय जनगणना कार्य निदेशालय के आदेशानुसार रायपुर नगर पालिक निगम के जोन क्रमांक 10 के अंतर्गत डॉ राजेन्द्र प्रसाद वार्ड क्रमांक 52 को छत्तीसगढ़ राज्य में जनगणना के लिए नगरीय क्षेत्र में प्री टेस्ट जनगणना पूर्व परीक्षण



हेतु चयनित किया गया है।

आज जनगणना निदेशालय के अधिकारी श्री हरीन्द्र सिंह ने नगर निगम जोन 10 के वार्ड 52 अंतर्गत कार्य का स्थल पर नगर निगम जोन 10 राजस्व विभाग और नगर निवेश विभाग की टीम सहित रायपुर

नगर निगम के आयुक्त श्री विश्वदीप के निर्देश पर नगर निगम जोन 10 द्वारा किये जा रहे कार्य की प्रगति का प्रत्यक्ष निरीक्षण नगर निगम जोन कमिश्नर श्री विवेकानंद दुबे, नोडल अधिकारी सहायक अभियंता श्री योगेश युटु, सहायक नोडल अधिकारी जोन

सहायक राजस्व अधिकारी श्री गौरीशंकर साहू की उपस्थिति में किया।

नगर निगम जोन 10 राजस्व विभाग और नगर निवेश विभाग की टीम के कर्मचारियों द्वारा वार्ड क्रमांक 52 क्षेत्र अंतर्गत स्थित सभी लगभग 8000 जनगणना भवनों में भवन संख्या डालने और भवनों को सूचीबद्ध करने का कार्य निरन्तर तेज गति से प्रगति पर है और लगभग 2500 भवनों में भवन संख्या डालने का कार्य किया जा चुका है, कार्य को तय समयसीमा के भीतर पूर्ण किया जाना है।

रायपुर नगर पालिक निगम ने नगर पालिक निगम जोन 10 के डॉ राजेन्द्र प्रसाद वार्ड क्रमांक 52 क्षेत्र की समस्त रहवासी जनता से प्री टेस्ट जनगणना पूर्व परीक्षण के कार्य में नगर पालिक निगम रायपुर जोन क्रमांक 10 के राजस्व विभाग और नगर निवेश विभाग की टीम को सभी लगभग 8000 जनगणना भवनों में भवन संख्या डालने और भवनों को सूचीबद्ध करने के कार्य में भारत सरकार गृह मंत्रालय जनगणना कार्य निदेशालय के आदेशानुसार किये जा रहे आवश्यक कार्य में सहयोग देने की एक बार पुनः विनम्र अपील की है।

पुलिस से बचने भाग रहा बदमाश का पैर टूटा

रायपुर, हिस्ट्रीशीटर बदमाश पुलिस को देखकर घर की छत से कूद गया। इस घटना में बदमाश के दोनों पैर टूट गए और वो गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मिली जानकारी के अनुसार, हिस्ट्रीशीटर बदमाश विक्की खोचड़ की गुंडागर्दी का एक वीडियो वायरल हुआ था। इस वीडियो में विक्की एक युवक को अपने दोस्तों और पत्नी के साथ जमकर पीटा था। इस वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपी विक्की खोचड़ के खिलाफमामला दर्ज किया था। वहीं जब आज सिविल लाइन पुलिस की टीम हिस्ट्रीशीटर बदमाश विक्की खोचड़ को गिरफ्तार करने पहुंची, तो आरोपी पुलिस को देखकर छत से कूद गया। छत से कूदने के कारण विक्की के दोनों पैर टूट गए और वो गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल विक्की को इलाज के लिए मेकाहारा अस्पताल में भर्ती करवाया गया है।

स्वच्छ भारत मिशन-शहरी 2.0 अन्तर्गत राज्योत्सव के अवसर पर रजत जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में

संवाददाता

रायपुर – छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस समारोह राज्योत्सव- 2025 का आयोजन 1 से 5 नवम्बर, 2025 तक किया जा रहा है। वर्ष 2025-26 राज्य के लिए ऐतिहासिक अवसर है। यह वर्ष छग. राज्य गठन के रजत जयंती वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। उक्त परिप्रेक्ष्य में राज्य शासन की मंशानुसार दिनांक 26 अक्टूबर से 9 नवम्बर 2025 तक विशेष स्वच्छता पखवाड़ा- 2025 का आयोजन किया जाना है। उपरोक्त अभियान के सफल क्रियान्वयन हेतु प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में उपमुख्यमंत्री नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग श्री अरूण साव के मार्गदर्शन में, राज्य के नगरीय निकाय क्षेत्र अंतर्गत दिशा निर्देश राज्य शहरी विकास अभिकरण ने दिये है।

रजत जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में विशेष स्वच्छता पखवाड़ा 2025 दिनांक 26 अक्टूबर से 9 नवंबर 2025 के दौरान राज्य



शासन की मंषा अनुसार राज्योत्सव 1 से 5 नवम्बर 2025 तक के आयोजन पर नगरीय निकाय क्षेत्र अंतर्गत रायपुर नगर पालिक

निगम क्षेत्र में आयोजन के संबंध में नगर पालिक निगम रायपुर की महापौर श्रीमती मीनल चैबे, स्वास्थ्य विभाग अध्यक्ष श्रीमती

गायत्री सुनील चंद्राकर, आयुक्त श्री विश्वदीप ने नगर निगम रायपुर के सभी 10 जोनों के जोन कमिश्नरों और जोन स्वास्थ्य

अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिये है।

राज्य शासन की मंषा अनुसार राज्य शहरी विकास अभिकरण के दिशा निर्देश अनुरूप विषेश स्वच्छता पखवाडा दिनांक 26 अक्टूबर से 9 नवंबर 2025 के आयोजन के अंतर्गत 26 अक्टूबर को घर घर जागरूकता अभियान, 27 व 28 अक्टूबर को नागरिको के सहयोग से स्वच्छता लक्षित इकाई में श्रमदान, 29 व 30 अक्टूबर को सफाई मित्र सुशुभा पवित्र का आयोजन, 31 अक्टूबर को वृक्षारोपण, 1 नवंबर को स्वच्छ रंगोली एवं इंटर

स्कूल प्रतियोगिता, 2 नवंबर को स्वच्छता श्रमदान, 3 नवंबर को स्वच्छ फूड स्ट्रीट, 4 नवंबर को स्वच्छ खेल महोत्सव, 5 व 6 नवंबर को एसएलआरएम सेन्ट्रो का खरखराव, 7 नवंबर को एसएलआरएम विजिट एवं वेस्ट टू आर्ट प्रदर्शन, 8 व 9 नवंबर 2025 को सार्वजनिक, सामुदायिक शौचालयों की सफाई से संबंधित सकारात्मक स्वच्छता गतिविधियों की जानी है।

छत्तीसगढ़ बंगाली मित्र समाज भिलाई में विजया मिलन समारोह का आयोजन किया

एजेंसी। छत्तीसगढ़ बंगाली मित्र समाज भिलाई कैप क्षेत्र के सदस्यों की ओर से बुधवार को कैम्प 2 विवेकानंद नगर बंगाली मोहल्ला हरि संघ काली मंदिर के प्रांगण एवं सामने स्थल पर विजया मिलन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में समाज के विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिष्ठित व्यक्ति सहित समाजबंधु शामिल हुए। इस समारोह में लोगों के द्वारा बड़ों के पैर छूकर आशीर्वाद लेते वहीं बड़ों के द्वारा छोटी को प्यार व दुलार देते हुए देखा गया तथा गुड के बनाए गए नारियल लड्डू एक दूसरे को खिलाया गया । दुर्गा पूजा के बाद बंगाली समाज का एक पारंपरिक यह उत्सव है। यह कार्यक्रम आमतौर पर दुर्गा पूजा के समापन के बाद होता है। लोग एक दूसरे के घर जाकर शुभकामनाएं देते है। यह आपसी भाईचारे और सौहार्द को बढ़ावा देने का अवसर है। आयोजन के इस मौके पर महिला सदस्यों के द्वारा कृष्णा मास के अवसर पर होने वाले सामूहिक पाठ का भी आयोजन तथा बांग्ला भाषा में गीत प्रस्तुति की गई । इस मौके पर सहभोज के साथ समाज के विकास के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई । कार्यक्रम में अतिथि के रूप में समाज के सुमित घोषाल, तपन दास, काजल चक्रवर्ती, अमिताभ सरकार, विद्युत चौधरी , डॉ मन्मूदादर , जितेन्द्र सरकार उपस्थित हुए तथा कार्यक्रम की अध्यक्षता छत्तीसगढ़ बंगाली मित्र समाज के प्रदेशाध्यक्ष सुमन शील ने की है। सम्बोधन के कड़ी में सर्वप्रथम काजल चक्रवर्ती ने बताया कि एक समय इस



क्षेत्र में एक मात्र दुर्गा पूजा हाउसिंग बोर्ड कालीबाड़ी में हुआ करता था जहां पर सुधन नगर, विवेकानंद नगर, शर्मा कॉलोनी के लोग एकत्रित होते थे क्योंकि एक कालीबाड़ी हुआ करता था । आज विभिन्न क्षेत्रों पर कालीबाड़ी बन गए हैं, जिससे लोग अपने अपने क्षेत्र में

बंधकर रह गए हैं परंतु हम सभी को एक जगह उपस्थित होने से कहीं ना कहीं एक दूसरे के सुख दुख का पता चल पाता है। लोगों को एक जगह बांधने का यह कार्य बंगाली बंधु समाज के द्वारा विजया मिलन समारोह के जरिए किया गया है। अपने अपने संबंधित में सभी

अतिथियों ने छत्तीसगढ़ बंगाली बंधु समाज से ज्यादा से ज्यादा जुड़ने का आह्वान किया है । कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे समाज के प्रदेशाध्यक्ष सुमन शील ने कहा कि समाज एक बड़ा व्यापक समूह है जो समान संबंधों कानून और संस्कृति को साझा करता है । समाज

विशाल होता है जिसमें कई समुदाय और विभिन्न प्रकार के लोग शामिल होते हैं । छत्तीसगढ़ में बंगाली समाज की आबादी 8वें प्रतिशत से अधिक होने के बावजूद आज भी बंगाली समाज अपने अधिकारों से वंचित है। उस वंचित को खत्म करने के लिए हमें एकजुट होने की आवश्यकता है । कार्यक्रम के अंत में भिलाई विधानसभा महिला विंग का अध्यक्ष श्रीमती तुलसी राय, वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र महिला विंग की अध्यक्ष काजल राय तथा वार्ड 33 विवेकानंद नगर कैप 2 महिला विंग की अध्यक्ष नर्मदा राय की घोषणा कर नियुक्ति पत्र सौंपा गया । समारोह में बंगाली दुर्गा पूजा समिति सुभाष नगर के संगम दुर्गा पूजा समिति के प्रभात राय, मिलन मजूमदार एवं शर्मा कॉलोनी सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति के नरेश शील, सुजित शील को स्मृति चिन्ह भेंटकर सम्मान किया गया तथा विवेकानंद नगर निवासी 80 वर्षीय श्रीमती अल्पना राय को बंगाली संस्कृति की अलख आने वाली पीढ़ी के साथ साझा करने वाली कार्य के लिए उपस्थित अतिथियों के हाथों से स्मृति चिन्ह देकर सम्मान कर आशीर्वाद लिया गया ।कार्यक्रम को सफल बनाने में मुख्य रूप से सुब्रत राय, सपन राय, राजेश सरकार, उत्तम विश्वास, सुशील पात्रों, मानिक शील, भूपति मण्डल, गणेश शील, रंजन प्रसाद, कोमल सरकार, चित्रा मण्डल , सुजाता सरकार, ममता पात्रों, नर्मदा राय, काजल राय का विशेष सहयोग रहा है ।

संपादकीय

चरमपंथी नक्सलवाद का अंत आवश्यक

बहरहाल, यह बहस का मुद्दा है कि माओवाद का यह पराभव सिर्फ सरकारी नजरिया बदलने के कारण हुआ है, या भारतीय राज्य के चरित्र एवं समाज की समझ संबंधी गलतियां माओवादियों को इस मुकाम तक ले आई हैं। विचारणीय है कि क्या राजनीति में अतिवादी दृष्टिकोण अपनाना और भारतीय राज्य के खिलाफ हर सामाजिक विभाजन रेखा का लाभ उठाने की उनकी रणनीति उनके लिए घातक साबित हुई? इस रणनीति के तहत धीरे-धीरे वे पहचान की



बिहार में विधानसभा चुनावों से प्रशांत किशोर को क्या उम्मीद है।

अजय दीक्षित

बिहार विधानसभा चुनावों में पहली बार भाग ले रही जनस्वराज पार्टी के मुखिया प्रशांत किशोर ने अमेरिका के एक टी वी चैनल एह्हह को बताया कि वह इस चुनाव में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए लड़ रहे हैं। उल्लेखनीय है कि बिहार विधानसभा चुनाव छह और ग्यारह नवंबर 2025 को होने वाले हैं।243 सीट की बिहार विधानसभा में मुख्य मुकाबला NDA और INDIA ब्लॉक के बीच है। वर्तमान में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली NDA सरकार है। 2020 के विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू,हम, लोकजनशक्ति, साथ हो कर चुनाव लड़े थे। भारतीय जनता पार्टी ने सर्वाधिक 74 सीट जीती थी जबकि जेडीयू ने 47 , राजद और कांग्रेस का महागठबंधन बहुमत से दूर रहा था।

अब बात करते हैं प्रशांत किशोर की वे देश में लाइम लाइट जब आए तब 2014 के लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत मिला।

और प्रशांत किशोर का नाम चुनाव विशेषज्ञ के रूप में सामने आया। प्रशांत किशोर बिहार के सहरसा जिले के रहने वाले हैं और इससे पहले विदेश में थे।

प्रशांत किशोर ने लगभग अरविन्द केजरीवाल की तरह राजनीति में प्रवेश किया।वे भी बिहार में रोजगार, पलायन,भाईभतीजाबाद, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में हैं। बिहार विधानसभा की कुल 243 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं लेकिन खुद उम्मीदवार नहीं हैं। बिहार में आजादी के बाद से ही जातिवाद, क्षेत्रवाद, नौकरशाही, जैसी राजनीतिक कुरीतियां का

बिहार : ‘वोट खरीद’ की विद्वरूपता के भरोसे

सत्येन्द्र रंजन

फिलहाल यही नजर आता है कि बिहार में 6 और 11 नवंबर को होने जा रहे मतदान एक सामान्य चुनाव का हिस्सा होंगे। इसमें कोई ऐसा नया तत्व नहीं है, जो मतदाताओं में नई आशाएं पैदा करे। प्रशांत किशोर नया तत्व जरूर हैं, मगर अरविंद केजरीवाल की यादें अभी इतनी ताजा हैं कि उनका नयापन कोई उम्मीद पैदा नहीं करता। तो कुल मिलाकर सूरत यह बनती है कि चुनावबाज दल, नेता, और मीडियाकर्म (हर चुनाव की तरह) इस चुनाव को लेकर जितने उत्साहित नजर आते हैं, वैसे उत्साह की कोई वजह आम जन को शायद ही नजर आती होगी !

बिहार के सबसे नए राजनीतिक उद्यमी प्रशांत किशोर को इसका श्रेय देना होगा कि उन्होंने विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सत्ताधारी एनडीए को सुशासन के दावे और भ्रष्टाचार के मुद्दे से वांचित कर दिया है। वरना, लालू-राबड़ी के कथित जंगल राज का हौवा खड़ा करना हर चुनाव में एनडीए की खास रणनीति रहती थी। ये दीगर बात है कि इस बार जंगल राज की याद दिलाने की सबसे ज्यादा कोशिश प्रशांत किशोर कर रहे हैं ! किशोर ने एनडीए नेताओं सम्राट चौधरी, अशोक चौधरी, दिलीप जायसवाल आदि पर गंभीर इल्जामों की झड़ी लगा रखी है। सुशासन का सिर्फ एनडीए को कठपौते में खड़ा दिखा है, बल्कि इस कारण सत्ताधारी गठबंधन की अंदरूनी दरारें भी सामने आई हैं। परिणाम यह हुआ है कि भाजपा- जनता दल (यू)- एलजेपी- हिंदुस्तानी आवाम पार्टी का गठबंधन पर भी तरह ‘वोट खरीद’ और सांप्रदायिक ध्ववीकरण पर निर्भर हो गया है।

सांप्रदायिक ध्रुवीकरण भाजपा की चुनावी रणनीति में मौजूद स्थायी तत्व है। पार्टी नेता कभी इसे पृष्ठभूमि में रखते हैं, तो कभी जरूरत के हिसाब से उसे आ रूप देते हैं। कई राज्यों में सिर्फ यही तत्व भाजपा को चुनाव जिताने में कारगर रहता आया है। मगर बिहार में अभी तक इसके निर्णायक होने का भरोसा शायद भाजपा नेतृत्व को नहीं है। इसीलिए नीतीश कुमार के मुछौटे की जरूरत उसे अभी भी है। नीतीश ढलान के दौर में हैं। बार-बार पाला बदलने से उनकी पुरानी छवि नष्ट हो चुकी है। सुशासन का नकाब उतर चुका है। उनकी सहैद को लेकर तमाम तरह की चर्चाएं हैं। फिर भी भाजपा उन्हें मुछौटा बनाए रखने पर मजबूर है, तो उसकी वजह अपनी ताकत पर पार्टी नेताओं का अविश्वास ही है।

नीतीश कुमार ने जो गंवाया है, उसकी चुनावी भरपाई उन्होंने मुक्त हाथ से सरकारी पैसा बांट कर करने की कोशिश की है। लगभग डेढ़ करोड़ परिवारों में महिलाओं के खाते में दस हजार रुपये का ट्रांसफर, लाखों युवाओं को दो साल तक हर महीने एक हजार रुपये का बेरोजगारी भत्ता, वृद्धावस्था एवं विकलांग पेंशन में भारी बढ़ोतरी, होमगार्ड के भत्तों में इजाफा, राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते की नई किस्त आदि जैसी कई घोषणाएं हैं, जिन्हें सीधे तौर पर ‘वोट खरीद’

राजनीति के इर्द-गिर्द गोलबंदी करने की हद तक चले गए, जिससे वे एक बंद गली में पहुंचे। इसी समय सरकार के नजरिए में आया बदलाव उन पर भारी पड़ा। नतीजा यह हुआ कि आखिरकार संवैधानिक दायरे के अंदर आने के लिए उन्हें मजबूर होना पड़ा है। साधारण तौर पर ‘वामपंथी चरमपंथ’ से ग्रस्त जिलों की संख्या 18 से घट कर 11 रह गई है। गुजरे एक साल में सैकड़ों माओवादी मारे गए हैं, गिरफ्तार हुए हैं या उन्होंने समर्पण कर दिया है।

जन्म हुआ लेकिन 1977 तक कांग्रेस सत्ता में बनी रही थी। 1977 में कर्पूरी ठाकुर नेता बनकर आए और मुख्यमंत्री बने उनके बाद भी कांग्रेस फिर सत्ता में आई,। जगन्नाथ मिश्र,भागवत झा आजाद मुख्यमंत्री बने ।1989 में जनतादल से लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बने उनका जादू 2004 में खत्म हुआ। प्रशांत किशोर पहली बार पलायन, गरीबी, बेरोज़गारी, जैसे मुद्दे नहीं उठा रहे हैं बल्कि लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार भी यही कहते हैं लेकिन बिहार से पलायन कभी नहीं रुका है यह तो आजादी से पहले से जारी है। क्योंकि बिहार की परिस्थितियों का अध्ययन करे तो पाया जाता है कि जातिगत शोषण एक विकराल समस्या है। बिहार में एक तबका जिसमें क्षत्रिय, भूमिहार, ब्राह्मण, और बनिया है जिसका सभी संसाधनों पर कब्जा है तो दूसरी ओर मुसलमान और यादव है जो बाहुबली है ।अब कुर्मी, निषाद,पासवान,अन्य अनुसूचित जाति है जो मजदूर और खेतिहर मजदूर भी है।ये ही लोग पहले बंगाल,अब मुंबई, दिल्ली की ओर भारी संख्या में जा बसे हैं। दिल्ली में तो पचास लाख बिहारी है जो रोजमर्रा का काम करते हैं जैसे ढकेल चलाना,रेडी, खोमचे वाले, ई रिक्शा, ऑटो इन्हीं के हवाले हैं जहां उन्हें रोजगार भी है और स्वाभिमान भी । प्रशांत किशोर चाहते हैं कि सरकार बिहार ऐसा बुनियादी ढांचा बनाए कि पलायन रुके । विश्व बैंक ने बिहार को सबसे फिसट्टी राज्य माना है जहां न रोजगार है न शिक्षा, न चिकित्सा।

सबसे बड़ी बात यह है कि कोई औद्योगिक विकास नहीं है क्योंकि उचित बातावरण नहीं है। यह निजी विचार है ।

रजनीश कपूर

भारत में संपत्ति विरासत के मुख्यतः दो आधार होते हैं। वसीयतनामा (विल) और उत्तराधिकार कानून (सक्सेशन लॉ)। यदि किसी व्यक्ति ने वैध वसीयत बनाई है, तब संपत्ति उसी के अनुसार बांटी जाती है। अगर वसीयत में कोई गड़बड़ी या विवाद है, या अगर वसीयत ही नहीं है, तो 1925 का इंडियन सक्सेशन एक्ट लागू होता है।ज संपत्ति और वसीयत पर शायद किसी ने खूब लिखा है, +अगर लिखोगे वसीयत अपनी, तो जान पाओगे ये हकीकत। तुम्हारी अपनी ही मिलिकयत में, तुम्हारा हिस्सा कहीं नहीं है।+•

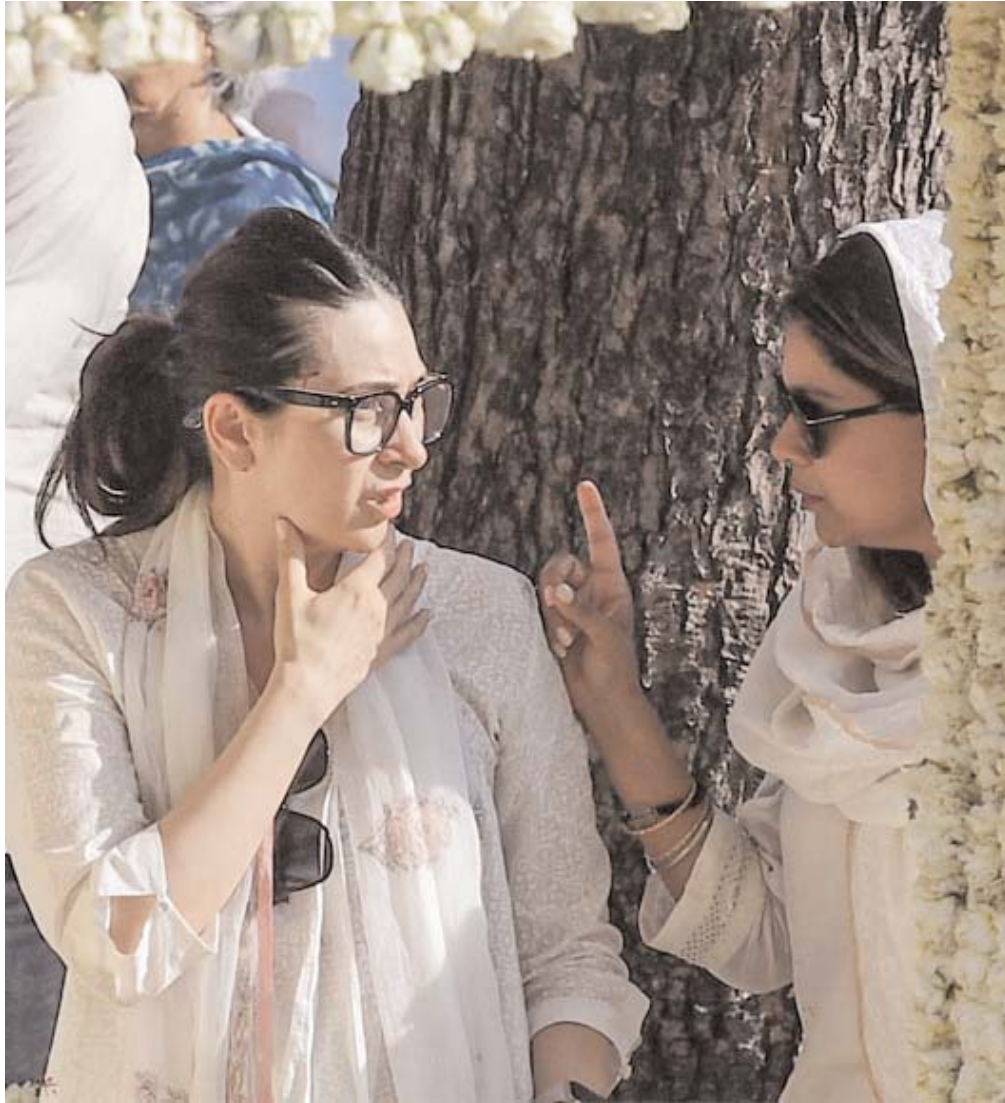
प्रसिद्ध लोगों की संपत्ति का बंटवारा अक्सर विवादों के घेरे में रहता है। हाल ही में करिश्मा कपूर और उनके पूर्व पति, उद्योगपति संजय कपूर की संपत्ति को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में चल रहे विवाद ने समाज और कानूनी व्यवस्था के कई पहलुओं को उजागर किया है। इस संपत्ति विवाद का विश्लेषण करने पर यह साफ़ होता है कि न सिर्फ़ कपूर परिवार बल्कि पूरे देश के अनेक धनी परिवारों में यह समस्या आम है और अक्सर इसमें परिवारजनों के निजी रिश्ते और कानूनी पेचिदगियां उलझ जाती हैं।

संजय कपूर की मौत के बाद उनकी संपत्ति, जिसका मूल्य लगभग 30,000 करोड़ रुपये आंका जाता है, को लेकर करिश्मा कपूर की बेटी समायरा और बेटा कियान ने अपनी सौतेली माँ प्रिया सचदेव कपूर और अन्य पर आरोप लगाया कि वे दोनों बच्चों के अधिकारों को हड़प रही हैं। उन्होंने कोर्ट में याचिका दायर की, जिसमें संजय कपूर के अंतिम वसीयत की वैधता को भी चुनौती दी गई है। बच्चों के वकील ने आरोप लगाया कि +वसीयत में गंभीर गलतियाँ हैं तथा उसे मरने के सात हफ्ते बाद ही प्रस्तुत किया गया।+•

बच्चों का कहना है कि उनके पिता ने उन्हें उनकी हिस्सेदारी का आश्वासन दिया था, लेकिन अचानक पेश की गई वसीयत में उनकी संपत्ति का कोई ज़िक्र नहीं है। दूसरी तरफ, प्रिया सचदेव कपूर की ओर से दावा किया गया है कि समायरा और कियान को पहले ही आर. के. परिवार ट्रस्ट के माध्यम से 1900 करोड़ रुपये दिये जा चुके हैं। लेकिन बच्चों के अनुसार उन्हें अभी तक उस धन की कोई भी किश्त नहीं मिली है। इस गंभीर कानूनी लड़ाई में संजय कपूर की माँ, रानी कपूर ने भी अपनी बहु प्रिया के विरुद्ध अदालत में आरोप लगाए हैं कि वसीयत में गड़बड़ी हुई है और उनकी सहमति के बिना संपत्ति का हस्तांतरण किया जा रहा है।

भारत में संपत्ति विरासत के मुख्यतः दो आधार होते हैं। वसीयतनामा (विल) और उत्तराधिकार कानून (सक्सेशन लॉ)। यदि किसी व्यक्ति ने वैध वसीयत बनाई है, तब संपत्ति उसी के अनुसार बांटी जाती है। अगर वसीयत में कोई गड़बड़ी या विवाद है, या अगर वसीयत ही नहीं है, तो 1925 का इंडियन सक्सेशन एक्ट लागू होता है। ज्यादातर संपत्ति विवाद इन स्थितियों में आते हैं, वसीयत की प्रमाणिकता (छेड़छाड़ या जबरन तैयारी), सभी वैध उत्तराधिकारियों को उनका ह्क़ न मिलना, वसीयत के कानूनी तकनीकी मुद्दे (साक्ष्य, गवाह, तिथि या चिकित्सीय स्थिति) या परिवार के भीतर भावनात्मक और सामाजिक टकराव।

सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में पारिवारिक संपत्ति विवादों पर फैसले दिए हैं, जो भारत में वसीयत और उत्तराधिकार कानून को स्पष्ट करते हैं। इनमें संयुक्त वसीयत की वैधता



और उत्तराधिकारियों को उचित हिस्सा देने के दिशा-निर्देश शामिल हैं। कुछ मामलों में अदालतों ने संयुक्त वसीयत को मान्यता देते हुए उत्तराधिकारियों को मुआवजा भी दिया है। संपत्ति विवाद को सुलझाने के लिए अदालत सबसे पहले वसीयत की प्रमाणिकता की जांच करती है। वसीयत को नियमित रूप से कानूनी तौर पर पंजीकृत होना चाहिए और उसके साक्ष्य होने चाहिए (गवाहों की उपस्थिति, दस्तावेज़ की तिथि, संपत्ति का स्पष्ट उल्लेख)। अगर वसीयत वैध साबित होती है, तो संपत्ति उसी के अनुसार बाँटी जाती है। यदि वसीयत साबित नहीं होती या कोई ग़लतफ़हमी होती है, तब अदालत उत्तराधिकार कानून के अनुसार बहनों, बच्चों, पत्नी, माता-पिता आदि को संपत्ति में समान हिस्सा देती है।

देश के कई अमीर और बड़े परिवारों में विरासत का विवाद पुराना है। अम्बानी, मोदी, ओबेरॉय, कपूर इत्यादि परिवारों में धन और वचस्व की लड़ाई कानून और मीडिया के केंद्र में आई है। मुख्य कारण हैं, परिवार में संवाद की कमी और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा, पारिवारिक ट्रस्ट और जटिल शैयख़धारिता संरचनाएँ, जिस व्यक्ति की सम्पत्ति है, उसकी अंतर्निहित इच्छा स्पष्ट न होना या कानूनी दस्तावेज़ों की तकनीकी गलतियाँ तथा खुदगर्जी।

इन घटनाओं से समाज और कानून के लिए कुछ

फिलहाल यह अनुमान लगाया जा सकता है कि जन सुराज पार्टी की उपस्थिति दर्ज होगी। किस हद तक- यह कहना अभी कठिन है। जन सुराज का दांव एनडीए और महागठबंधन- दोनों से वोट छीनने पर टिका है। इस मिलसिले में उसकी ध्वनियों का प्रभाव देखा गया है। मगर मतदान का निर्णय अंततः कई अन्य पहलुओं से तय होता है। सांप्रदायिक ध्रुवीकरण से प्रभावित मतदाताओं का भाजपा के सोये में खुद को ‘सुरक्षित’ महसूस करना इस वक्त ऐसा एक पहलू है। ‘संविधान और सामाजिक सद्भाव बचाने’ के लिए भाजपा को किसी कीमत पर हरना एक दूसरा पहलू है। बिहार में गुजरे तीन दशकों से लालू समर्थन और विरोध भी ऐसे पहलू रहे हैं। ऐसे सामाजिक वर्गों के मतदाता बड़ी संख्या में मौजूद हैं, जो लालू राज के दौरान हुए अपने ‘सशक्तीकरण’ का याद रखे हुए हैं।

क्या प्रशांत किशोर की ध्वनियां इन तमाम पहलुओं को मात दे पाएंगी? या उन ध्वनियों का असर सीमित रहेगा, नतीजतन जन सुराज वोट कटवा अधिक भूमिका नहीं निभा पाएंगी? वह सबसे ज्यादा किसके वोट काटेगी? क्या बिहार में बदलाव चाने वाले मतदाताओं के एक हिस्से को आकर्षित कर यह सत्ताधारी गठबंधन की मददगार बनेगी? अथवा, नीतीश कुमार से ऊबे ऐसे मतदाताओं को यह अपनी ओर खींचेंगी, जो लालू यादव से नाराजगी के कारण महा-गठबंधन को वोट नहीं देते और इस रूप में यह महा-गठबंधन की सहायता करेगी? ये सब ऐसे सवाल हैं, जिन पर बिहार चुनाव के पूरे दौर में चर्चा जारी रहने वाली है।

फिलहाल, जो नजर आता है, वो यह है कि सत्ताधारी गठबंधन की संभावनाएं सांप्रदायिक ध्रुवीकरण और ‘वोट खरीदो’ योजना के सफलता पर टिकी हुई हैं। सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के अंदर विभिन्न जातियों को प्रतिनिधित्व देकर भाजपा ने जो ‘सोशल इंजीनियरिंग’ देश के ज्यादातर हिस्सों में की है, बिहार उससे अलग नहीं है। एनडीए में नीतीश कुमार को मिली अहमियत खुद उसी ‘सोशल इंजीनियरिंग’ का हिस्सा है। फिलहाल, इस रणनीति के कमजोर पड़ने के संकेत नहीं हैं। इसीलिए ‘सुशासन’ जैसे दावों के बेनकाब होने, भ्रष्टाचार का मुद्दा हाथ से निकलने और विकास के मोर्चे पर तमाम नाकामियों के बावजूद इस चुनाव में एनडीए की pole position (दौड़ में अग्रिम स्थान) कायम नजर आती है।

दूसरी तरफ महा-गठबंधन अपने सीमित सामाजिक समीकरण के साथ एंटी-इन्कबैंसी के भरोसे ही है। महा-गठबंधन के प्रमुख दल- आरजेडी का अपना सामाजिक आधार मजबूत बना रहा है। सिर्फ इस समीकरण की ताकत के आधार पर उसे लगभग एक चौथाई वोट मिल जाते रहे हैं। इसके साथ एंटी-इन्कबैंसी का पहलू जुड़े, तो आरजेडी अपने साथी दलों- कांग्रेस, लेफ्ट, विकासशील इनसान पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा आदि के साथ सत्ता के करीब पहुंच सकता है। मगर एक तरफ रुपयों की बारिश कर नीतीश कुमार सरकार ने और दूसरी तरफ इंटी-इन्कबैंसी वाले वोट का एक और दावेदार बन कर जन सुराज ने महा-गठबंधन की संभावनाओं के बारे में अस्पष्टता पैदा कर दी है।

महा-गठबंधन के सामने सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि उसके नेतृत्व ने जिस प्रमुख मुद्दे के सहारे

मतदाताओं को लुभाने की योजना बनाई, चुनाव आने से पहले ही सत्ता पक्ष ने उससे उन्हें वांचित कर दिया। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने जातीय जनगणना की मांग के इर्द-गिर्द बिहार में चुनाव लड़ने की मंशा दिखाई थी। मगर केंद्र सरकार ने अगली जनगणना में जातीय गिनती को शामिल कर इसे मुद्दे की धार भोथरी कर दी।

उसके बाद राहुल गांधी ने ‘वोट चोरी’ को अपने अभियान का केंद्रीय बिंदु बनाया। विपक्ष के कार्यकर्ताओं और समर्थकों को लामबंद करने में यह मुद्दा कामयाब रहा है, लेकिन आम जन के स्तर पर इसका असर है, इसके शायद ही कोई संकेत है। इसकी एक बड़ी वजह मीडिया नैरेटिव पर सत्ता पक्ष का नियंत्रण है, मगर इसका एक कारण यह भी है कि ऐसे मुद्दे रोजी-रोटी के रोजमर्रा के सवालों में उलझे जन समुदायों के मन को अक्सर छू नहीं पाते। इसलिए ऐसे मसले मध्य वर्ग के बीच और सोशल मीडिया पर जो ध्वनि निर्मित करते हैं, वह जमीनी स्तरों तक नहीं पहुंच पाती है।

सार यह कि महा-गठबंधन के पास ऐसे मुद्दे का स्पष्ट अभाव है, जिससे वह मतदाताओं में अपने प्रति उत्साह पैदा कर पाए। खुद महा-गठबंधन के घटक दलों- खासकर कांग्रेस- ने भी अपनी राह को मुश्किल बनाने में पर्याप्त योगदान किया है। अपनी असल ताकत से अधिक सीटों की मांग और आखिरी वक्त तक तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करने से इनकार कर कांग्रेस ने महाराष्ट्र वाली गलती बिहार में दोहराई है। कुछ ऐसा ही रोल मुकेश सहनी की विकासशील इनसान पार्टी का भी है।

पांच साल पहले तेजस्वी यादव ने रोजगार को अपना प्रमुख चुनावी मुद्दा बनाया था। तब वे नया चेहरा थे। तब उन्होंने खुद को सभी जातियों और समुदायों के नेता के बतौर पेश किया और ऐसे मुद्दे उठाए, जिनका संबंध सबसे है। चुनाव नतीजों से जाहिर हुआ कि यह रणनीति कामयाब रही। मगर उसके बाद नीतीश कुमार के पाला बदल में सहायक बन कर तथा छोटी अवधि की उनकी गठबंधन सरकार में शामिल होकर तेजस्वी ने नूतनता का तेज गंवा दिया। मतदाताओं के सामने अब उनकी उपस्थिति एक आम नेता के रूप में है। लाजिमी है कि उत्साह पैदा करे। प्रशांत किशोर नया तत्व जरूर हैं, मगर अरविंद केजरीवाल की यादें अभी इतनी ताजा हैं कि उनका नयापन कोई उम्मीद पैदा नहीं करता। तो कुल मिलाकर सूरत यह बनती है कि चुनावबाज दल, नेता, और मीडियाकर्म (हर चुनाव की तरह) इस चुनाव को लेकर जितने उत्साहित नजर आते हैं, वैसे उत्साह की कोई वजह आम जन को शायद ही नजर आती होगी !

यह निजी विचार है।

एआई अपनाने में तेजी लाने के लिए ‘कृषि और एसएमई के लिए एआई प्लेबुक’ और ‘एआई सैंडबॉक्स श्वेत पत्र’ लॉन्च

पीआईबी

भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार (पीएसए) प्रो. अजय कुमार सूद ने विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) के चौथे औद्योगिक क्रांति केंद्र (सी4आईआर) इंडिया द्वारा संचालित ‘भारत के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता 2030+’ पहल के अंतर्गत तीन पुस्तिकाओं का विमोचन किया। इसकी घोषणा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी सचिव श्री एस. कृष्णन, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) सचिव श्री एससीएल दास, प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय (ओपीएसए) के वैज्ञानिक सचिव डॉ. परविरद मैनी और कृषि मंत्रालय के सलाहकार (डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर) श्री अनिल बनर्जी की उपस्थिति में की गई। इन तीन पुस्तिकाओं में शामिल हैं:

‘भारत में भविष्य की खेती: कृषि के लिए एआई प्लेबुक’

‘छोटे व्यवसायों का रूपांतरण: भारत के एसएमई के लिए एक एआई प्लेबुक’

‘इंटेलिजेंट एज के लिए एआई सैंडबॉक्स इको-सिस्टम को आकार देना: श्वेत पत्र’

ओपीएसए और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के मार्गदर्शन में शुरू की गई और एक बहु-हितधारक सलाहकार परिषद द्वारा संचालित, एआई फॉर इंडिया 2030 पहल का उद्देश्य कार्यानीतिक और वैश्विक प्रासंगिकता के साथ संरचना का विकास करना है, जो भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था के केंद्र में उत्तरदायी, समावेशी और परिमाण-आधारित एआई को रखता है।

पीएसए प्रो. सूद ने कहा, ‘भारत की एआई यात्रा जमीनी स्तर पर बदलाव से निर्धारित होती है। ये प्लेबुक समयोचित हैं और एआई को समावेशी तथा प्रभावशाली बनाने के लिए स्पष्ट कार्यनीतियां प्रदान करती हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि प्रौद्योगिकीय प्रगति हमारे किसानों, उद्यमियों और देश भर के समुदायों के लिए वास्तविक लाभ में परिवर्तित हो। मैं सभी हितधारकों से आग्रह करता हूं कि वे राष्ट्र के विकास के लिए इन क्रियाशील रोडमैप को लागू करने में सामूहिक रूप से काम करें। इन रिपोर्टों में परिलक्षित विभिन्न विभागों और पहलों का संयोजन निरंतर गति में परिवर्तित होना चाहिए और समाज में एआई को व्यापक रूप से अपनाने में मदद करनी चाहिए।’



ये प्लेबुक भारत के महत्वपूर्ण सेक्टरों में एआई समाधानों को लागू करने के लिए व्यावहारिक रोडमैप प्रदान करती हैं, जो व्यापक क्षेत्रीय परामर्शों, पायलट परियोजनाओं और सरकार, उद्योग, स्टार्ट-अप्स, शैक्षणिक संस्थानों और किसान संगठनों से प्राप्त इनपुट पर आधारित हैं। प्रत्येक पुस्तिका में एक सहयोगी मॉडल शामिल है जो सरकार, उद्योग और स्टार्ट-अप्स तथा सभी हितधारकों की भूमिकाओं को परिभाषित करता है। डब्ल्यूईएफ के सी4आईआर इंडिया के प्रमुख श्री पुरुषोत्तम कौशिक ने जारी किए गए प्रकाशनों का संक्षिप्त सारांश और कार्यप्रणाली प्रस्तुत की।

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी सचिव श्री कृष्णन ने कहा,

‘वास्तविक सेक्टरों पर केंद्रित इन रिपोर्टों के साथ, हमारे पास एक बहुत अच्छा संकलन है, जो विभिन्न हितधारकों की भागीदारी से तैयार हुआ है और भावी परिदृश्य दिखाता है। यह प्लेबुक दर्शाती है कि कैसे एआई को इस परिवर्तन में सहजता से शामिल किया जा सकता है- जिससे नई दक्षताएं, बेहतर निर्णय लेने की क्षमता और प्रत्येक किसान के लिए अधिक समृद्धि संभव हो सकती है।’

‘भारत में भविष्य की खेती’ पुस्तिका लाखों किसानों के लिए एआई के विस्तार की रूपरेखा प्रस्तुत करती है, जिसका उद्देश्य उपज बढ़ाना, जोखिमों का प्रबंधन करना और बाजार पहुंच में सुधार करना है। इसका मूल इम्पैक्ट एआई ढांचा है, जो सहयोग का मार्गदर्शन करता

एनएचएआई देश भर में 20,000 किलोमीटर से अधिक राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए नेटवर्क सर्वेक्षण वाहन तैनात करेगा

पीआईबी। राष्ट्रीय राजमार्गों पर यात्रियों को बेहतर यात्रा अनुभव प्रदान करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) 23 राज्यों में नेटवर्क सर्वेक्षण वाहन (एनएसवी) तैनात करेगा, जो राष्ट्रीय राजमार्गों के विभिन्न हिस्सों की सड़क सूची और पुरपाथ की स्थिति के आंकड़ों के संग्रह, प्रसंस्करण और विश्लेषण के लिए 20,933 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। एनएसवी की तैनाती से एनएचएआई को सड़क सूची और पुरपाथ की स्थिति से संबंधित आवश्यक आंकड़े- जिसमें सतह पर दरारें, गड्ढे और पैच आदि जैसी सभी संबंधित सड़क खामियां शामिल हैं- एकत्र करने में मदद मिलेगी। एनएसवी सर्वेक्षणों के माध्यम से एकत्र किए गए आंकड़े सड़क की स्थिति की कमियों को उजागर करेंगे, जिससे एनएचएआई राष्ट्रीय राजमार्गों के बेहतर रखरखाव के लिए सुधारात्मक उपाय करने के लिए प्रेरित होगा।

एनएसवी सर्वेक्षण के माध्यम से एकत्रित डेटा को एनएचएआई के ‘एआई’ आधारित पोर्टल डेटा लेक पर अपलोड किया जाएगा, जहां एनएचएआई के विशेषज्ञों की एक समर्पित टीम द्वारा इसका विश्लेषण किया जाएगा ताकि डेटा को ज्ञान और उसके बाद कार्रवाई योग्य अंतर्दृष्टि में बदला जा सके। अंततः भारत सरकार के दिशानिर्देशों के



अनुसार नियमित अंतराल पर एकत्रित डेटा को भविष्य के तकनीकी उद्देश्यों के लिए निर्धारित प्रारूपों में सड़क परिसंपत्ति प्रबंधन प्रणाली में संरक्षित किया जाएगा।

पुरपाथ की स्थिति का सर्वेक्षण 3डी लेजर आधारित एनएसवी प्रणाली का उपयोग करके किया जाएगा, जो उच्च रिज़ोल्यूशन वाले 360-डिग्री कैमरों, डीजीपीएस (डिफ़ेंशियल ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम), आईएमयू (इनर्शियल मेजरमेंट यूनिट) और डीएमआई (डिस्टेंस मेजरिंग इंडिकेटर) की मदद से बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के सड़क की खामियों को स्वचालित रूप से पकड़ने और रिपोर्ट करने में सक्षम है। ये सर्वेक्षण बहुमुखी डेटा अधिग्रहण और प्रसंस्करण सॉफ्टवेयर से लैस हैं ताकि इन्वेंट्री और पुरपाथ की स्थिति के आंकड़ों को सटीक रूप से मापा और रिपोर्ट किया जा सके।

लद्दाख की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए जीएसटी सुधार

पीआईबी

10,000+ कारीगरों की मदद के लिए पश्मीना, नमदा गलीचे और लकड़ी से बनी शिल्प कलाकृतियों पर 5 प्रतिशत जीएसटी । जीएसटी कम होने से डेयरी और जैविक खेती में बेहतर आय और प्रतिस्पर्धात्मकता देखी जा रही है; खुबानी की खेती में लगे 6,000+ किसान परिवारों को लाभ होगा

यात्रा को अधिक किफायती बनाने और 25,000+ लोगों की आजीविका को बनाए रखने के लिए होटल टैरिफ पर 5 प्रतिशत जीएसटी = 7,500 रुपये निर्धारित । लद्दाख में स्वावलंबन को बढ़ावा देने के लिए याक डेयरी, ऊन उत्पादकों और जैविक खेती को समर्थन देने के लिए जीएसटी में कटौती

परिचय लद्दाख की अर्थव्यवस्था अपने अद्वितीय भूगोल, संस्कृति और शिल्प कौशल में गहराई से निहित है। यहां पारंपरिक आजीविका उभरते



पर्यावरण के अनुकूल उद्योगों के साथ जुड़ी हुई है। उच्च गुणवत्ता वाले पश्मीना ऊन और खुबानी के बागों से लेकर जटिल थांका पेंटिंग और टिकाऊ पर्यटन तक, प्रत्येक क्षेत्र क्षेत्र के कौशल और विरासत को दर्शाता है।

उत्पादों और सेवाओं की विस्तृत विविधता की श्रेणी में हाल ही में जीएसटी में कटौती से लद्दाख की समृद्ध अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ेगा और इससे कारीगरों, किसानों और छोटे उद्यमों को राहत मिलेगी। साथ ही ये सुधार आजीविका सृजन,

सांस्कृतिक संरक्षण और लद्दाख की अर्थव्यवस्था के सतत विकास का समर्थन करेंगे।

हथकरघा पश्मीना ऊन और उत्पाद लद्दाख के सबसे मूल्यवान पारंपरिक शिल्पों में से एक, पश्मीना ऊन का उत्पादन लेह के चांगथांग क्षेत्र में किया जाता है। इससे 10,000 से अधिक खानाबदोश चरवाहों का जीवन यापन होता है। पश्मीना अपनी गर्मी, कोमलता और सुंदरता के लिए जानी जाती है, और इसका उपयोग प्रीमियम शॉल, स्टोल और अन्य वस्त्रों के लिए किया जाता है।

जीएसटी को 12 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत करने से उत्पादन लागत कम करने में मदद मिलती है और पारंपरिक हस्तशिल्प तौर-तरीकों में सुधार को प्रोत्साहित किया जाता है। इससे ऊन प्रसंस्करण और गलीचा बनाने में लगे स्थानीय कारीगरों और सहकारी समितियों को महत्वपूर्ण लाभ मिलने की उम्मीद है।

ऊनी फेल्ट उत्पाद और ऊनी सहायक उपकरण लेह और चांगथांग के ऊन महसूस किए गए उत्पाद और ऊनी सामान, जैसे कि फेल्ट जूते, टोपी और दस्ताने, लद्दाख की पारंपरिक शिल्प संस्कृति को बढ़ाते हैं। इन वस्तुओं का उपयोग स्थानीय रूप से किया जाता है और और ये पर्यटकों के बीच भी खरीददारी के लिए लोकप्रिय हैं। जीएसटी को 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने से ऊन प्रसंस्करण और उत्पाद निर्माण में लगे छोटे पैमाने पर, मौसमी कूटीर उद्योगों को सहायता मिलती है । इससे कारीगरों की आय में वृद्धि के साथ लद्दाख की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की भी उम्मीद है।



(22कैप्शन11)केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ नई दिल्ली में संसद भवन में भारत के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति श्री सी. पी. राधाकृष्णन से मुलाकात की।



उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन और पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद अपने परिवार के साथ रविवार, 19 अक्टूबर, 2025 को नई दिल्ली स्थित उपराष्ट्रपति एन्क्लेव में दिवाली की शुभकामनाएं देते हुए।

गति से प्रणालीगत मजबूती की ओर अगली बड़ी छलांग से विकासशील भारत को मिलेगी नई शक्ति

एमएनआरई ने स्थिर, विश्वसनीय और सतत नवीकरणीय विकास सुनिश्चित करते हुए भारत के तीव्र विस्तार से लेकर प्रणालीगत एकीकरण तक के परिवर्तन को रेखांकित किया

भारत के 2030 स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों को कार्यानीतिक स्थायित्व के साथ आगे बढ़ाने के लिए ग्रिड, वित्तीय प्रणालियों और बाजार डिजाइन के साथ नवीकरणीय ऊर्जा का समन्वयन किया

हाइब्रिड और आरटीसी परियोजनाओं, अपतटीय पवन, भंडारण, पीएम कुसुम और पीएमएसजीवाई के तहत वितरित सौर, ग्राम इडलीजन और ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के साथ आकार ले रहा है भारत के नवीकरणीय विकास का अगला चरण

पीआईबी

भारत का नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र एक नए रूपान्तरकारी चरण में प्रवेश कर रहा है, जो न केवल क्षमता वृद्धि की गति से

बल्कि इसकी प्रणालियों की मजबूती, स्थिरता और गहनता से भी परिभाषित होगा। एक दशक के रिकॉर्ड विस्तार के बाद, अब फेकस मजबूत, वितरण योग्य और लचीली स्वच्छ ऊर्जा संरचना के निर्माण पर केंद्रित है जो 2030 तक 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म क्षमता प्राप्त करने के देश के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक हो सके।

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) ने रेखांकित किया है कि भारत की नवीकरणीय विकास की गाथा विश्व में सबसे तेज और सबसे अग्रगामी बनी हुई है, जो गति से लेकर प्रणाली की मजबूती, मात्रा से लेकर गुणवत्ता और विस्तार से लेकर स्थायी एकीकरण तक विकसित हो रही है।

मात्रा से गुणवत्ता की ओर बदलाव पिछले दशक में भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता पांच गुना से भी अधिक बढ़ी है, जो 2014 में 35

गीगावाट से कम थी और आज 197 गीगावाट (बड़ी जलविद्युत परियोजनाओं को छोड़कर) से भी अधिक हो गई है। यह असीम वृद्धि अनिवार्य रूप से एक ऐसे बिंदु पर पहुंचती है, जहां आले के कदम के लिए न केवल अधिक मेगावाट की आवश्यकता होगी, बल्कि गहन प्रणाली सुधारों की भी जरूरत होगी। यह सेक्टर उस चरण में प्रवेश कर चुका है, जहां फेकस क्षमता विस्तार से हटकर क्षमता अवशोषण पर केंद्रित हो रहा है। अब हम ग्रिड एकीकरण, ऊर्जा भंडारण, संकरण और बाजार सुधारों पर काम कर रहे हैं, जो 500 गीगावाट से अधिक के गैर-जीवाश्म भविष्य की वास्तविक नींव हैं। इस अर्थ में क्षमता वृद्धि में हाल में आई नरमी एक पुनर्संतुलन है, एक आवश्यक विराम है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि भविष्य का विकास स्थिर, प्रेषण योग्य और लचीला हो।

भारत की नवीकरणीय ऊर्जा वृद्धि विश्व में सबसे तेज बनी हुई है, जो बहु-

मागीय विस्तार से प्रेरित है

40 गीगावाट से अधिक की नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं वर्तमान में पीपीए, पीएसए या ट्रांसमिशन कनेक्टिविटी अर्जित करने के उन्नत चरणों में हैं - जो इस क्षेत्र में प्रतिबद्ध निवेश की मजबूत पाइपलाइन का स्पष्ट प्रतिबिंब है। वास्तविकता यह है कि भारत का नवीकरणीय ऊर्जा बाजार अपने ग्रिड और सविदात्मक संस्थानों की गति से आगे निकल गया है, जो व्यापक स्तर पर ऊर्जा परिवर्तन से गुजर रहे सभी देशों के लिए एक समान चुनौती है।

इस संदर्भ में, नवीकरणीय ऊर्जा के लिए व्यापक पर बोलियां लगाने से पहले राज्यों/डिस्कॉम द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा खरीद दायित्व को लागू करना, बिजली की निकासी के लिए ट्रांसमिशन लाइनों को उन्नत करना और ग्रिड एकीकरण के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करना शीर्ष प्राथमिकताएं बनी हुई हैं।

चालू वर्ष में केंद्रीय नवीकरणीय

ऊर्जा कार्यान्वयन एजेंसियों (आरईआईए) ने 5.6 गीगावाट के लिए बोलियां लगाई हैं, जबकि राज्य एजेंसियों ने 3.5 मेगावाट के लिए बोलियां लगाई हैं। इसके अतिरिक्त, वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं द्वारा कैलेंडर वर्ष 2025 में लगभग 6 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता जोड़ने की संभावना है। इस प्रकार, नवीकरणीय ऊर्जा की क्षमता वृद्धि न केवल आरईआईए द्वारा संचालित बोलियों के माध्यम से, बल्कि कई माध्यमों से हो रही है। वैश्विक प्रतिकूल परिस्थितियों ने भी इसमें भूमिका निभाई है: आपूर्ति-श्रृंखला में व्यवधान, मॉड्यूल की कीमतों में उतार-चढ़ाव और कठिन वित्तीय परिस्थितियों ने कमीशनिंग की समय-सीमा को धीमा कर दिया है। फिर भी, भारत वार्षिक रूप से 15-25 गीगावाट नई नवीकरणीय क्षमता जोड़ना जारी रखे हुए है, जो विश्व में सबसे तेज़ दरों में से एक है।

एनएचआरसी ने तीनों राज्यों के पुलिस महानिदेशकों को नोटिस जारी की, दो सप्ताह में मामले की विस्तृत रिपोर्ट मांगी

पीआईबी

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने 30 अगस्त, 2025 को केरल और मणिपुर तथा 21 सितंबर, 2025 को त्रिपुरा में अलग-अलग स्थानों पर तीन पत्रकारों पर हुए हमले के बारे में मीडिया रिपोर्टों का स्वतः संज्ञान लिया है। एनएचआरसी ने तीनों मामलों में तीनों राज्यों के पुलिस महानिदेशकों को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर मामले की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।

कथित तौर पर, त्रिपुरा में एक पत्रकार पर कुछ बदमाशों ने लाठियों और धारदार हथियारों से उस समय हमला किया जब वह पश्चिमी त्रिपुरा के हेज़ामारा इलाके में एक राजनीतिक दल के वस्त्र वितरण कार्यक्रम में शामिल हो रहे थे। उनकी मोटरसाइकिल भी चोरी कर ली गई। मणिपुर में सेनापथी ज़िले के लाई गांव में एक पुष्प उत्सव की कवरेज के दौरान एक पत्रकार पर हमला किया गया। उन्हें एयर गन से दो बार गोली मारी गई जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। केरल में, थैटुपुज़ा के पास मंगट्टुक्कवाला पहुंचने पर एक पत्रकार पर लोगों के एक समूह ने हमला किया। वह एक शादी समारोह से लौट रहे थे। बताया जा रहा है कि तीनों ही मामलों में पीड़ितों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया और पुलिस ने मामले दर्ज कर लिए हैं।

गोवर्धन पूजा और अन्नकूट से शुरू हुआ पर्व, आदिवासी समाज ने धूमधाम से मनाया गौरा-गौरी

ग्राम धामनसरा में दीपावली से गौरा-गौरी तक उत्सव का रंग

राजनांदगांव। ग्राम धामनसरा में इस वर्ष दीपावली की खुशियों की श्रृंखला पूरे जोरों पर रही। दीपावली के अवसर पर घरों और आंगनों में दीपों और रंगोली से सजावट की गई और मंदिरों में श्रद्धा और भक्ति के साथ पूजा-अर्चना की गई।

गोवर्धन पूजा और अन्नकूट का आयोजन

दीपावली के दूसरे दिन ग्रामीणों ने भगवान श्रीकृष्ण की पूजा कर गोवर्धन पर्वत का प्रतीक स्थापित किया। महिलाओं ने पारंपरिक रीति-रिवाज से अन्नकूट तैयार कर भगवान को अर्पित किया। भजन-कीर्तन और प्रसाद वितरण ने पूरे दिन वातावरण को भक्तिमय बना दिया।

आदिवासी धुव गोंड समाज का उत्सव

इसके बाद आदिवासी धुव गोंड समाज ने बड़े उत्साह के साथ गौरा-गौरी पर्व मनाया। समाज के सदस्य कोमल शोरी, अर्जुन शोरी, संजय शोरी, महेन्द्र शोरी, गुमान चिता मंडवी, पीलु मंडवी, तरुण मंडवी सहित अन्य समाजिक बंधु उपस्थित रहे। सभी ने पारंपरिक आदिवासी वेशभूषा धारण कर नृत्य और गीतों के माध्यम से अपनी संस्कृति का

ग्राम आलीखुटा में पुलिस स्मृति दिवस मनाया गया



राजनांदगांव। ग्राम आलीखुटा में मंगलवार को पुलिस स्मृति दिवस बड़े श्रद्धाभाव और सम्मान के साथ मनाया गया। इस अवसर पर ग्राम के वीर सपूत शहीद जगतराम कंवर के स्मारक स्थल पर श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। जिसमें क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों, शिक्षकों, किसान कांग्रेस पदाधिकारियों और ग्रामीणों ने शहीद को नमन किया।

कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित किसान कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मदन साहू जनपद सदस्य श्रीमती सरिता साहू शासन

ग्राम तोरणकट्टा में लोक परब का मव्य आयोजन 23 अक्टूबर को

राजनांदगांव। शहर से सटे ग्राम तोरणकट्टा में 23 अक्टूबर को पारंपरिक मातर एवं लोक परब का आयोजन किया जा रहा है। ग्राम पंचायत के सरपंच सैन जनक उड़क ने बताया कि कार्यक्रम में रात्रि के समय लोगों के मनोरंजन हेतु छत्तीसगढ़ी सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें ग्राम जंगलपुर, पाड़ादाह तथा संगीत नगरी खैरागढ़ के कलाकार अपनी प्रस्तुति देंगे। कार्यक्रम की तैयारी जोर-शोर से की जा रही है। आयोजन में उप सरपंच रंखलाल साहू, बबलू यादव, होरी यादव, गोकुल साहू, हेमंत साहू एवं विजय चंद्राकर की सक्रिय भूमिका रहेगी।

दीपावली और गौरा-गौरी विवाह पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया

राजनांदगांव। परिवार जब साथ होता है तो हर पर्व का आनंद दोगुना हो जाता है। राजनांदगांव की भुवनेश्वरी सिन्हा का परिवार इसी एकता और प्रेम का उदाहरण बन गया है। चाहे दीपावली हो या गौरा-गौरी विवाह, सिन्हा परिवार हर अवसर पर पूरे हर्षोल्लास के साथ एकत्रित होकर परंपराओं को सहेजता है।

इस वर्ष दीपावली के अवसर पर भुवनेश्वरी सिन्हा अपने चारों



पुत्रों, बहुओं और नाती-पोतों के साथ दीपों की जगमग रोशनी में खुशियां मनाते नजर आए। परिवार के सभी सदस्य पारंपरिक परिधान में एक साथ पूजा-अर्चना कर सामाजिक एकता



सुंदर प्रदर्शन किया।

जीवनदायिनी शिवनाथ नदी में विसर्जन

उत्सव का kulmination

जीवनदायिनी शिवनाथ नदी में गौरा-गौरी के विसर्जन के साथ हुआ। ढोल-मांदर की थाप, भक्ति गीत और ग्रामीणों की उपस्थिति ने पूरे माहौल

को उल्लासपूर्ण और भक्तिमय बना दिया।

समाज और संस्कृति का संदेश इस प्रकार ग्राम धामनसरा में

दीपावली, गोवर्धन पूजा और गौरा-गौरी पर्व की श्रृंखला ने भक्ति, संस्कृति और सामाजिक एकता का संदेश दिया।

ग्राम डोडिया में गौरा-गौरी का विसर्जन उत्साहपूर्वक सम्पन्न



विधिवत पूजा-अर्चना के बाद निकली मव्य शोभायात्रा, ग्राम में छाया उल्लास का माहौल

राजनांदगांव। जिले से लगे ग्राम डोडिया में पारंपरिक गौरा-गौरी विसर्जन समारोह बड़े ही हर्षोल्लास और श्रद्धा के साथ सम्पन्न हुआ।

ग्रामवासियों ने विधिवत पूजा-अर्चना कर गौरा-गौरी की प्रतिमाओं का पूजन किया, तत्पश्चात ढोल-नगाड़ों, मंजीरों और गीत-संगीत के बीच भव्य शोभायात्रा निकाली गई।

पूरे ग्राम में भक्ति और उल्लास का माहौल देखने को मिला। महिलाएँ पारंपरिक परिधान में नाच-गान करती हुई शोभायात्रा में शामिल रहीं, वहीं युवा वर्ग ने भी पूरे जोश के साथ

भाग लिया। कार्यक्रम में ग्राम सरपंच, जनप्रतिनिधि तथा ग्रामीणों की विशेष उपस्थिति रही। आयोजन में महिला समूहों, युवाओं और ग्राम समितियों का विशेष सहयोग रहा। शोभायात्रा के समापन पर विधिवत रूप से गौरा-गौरी का विसर्जन किया गया और सभी ने ग्राम की सुख-समृद्धि की कामना की।

खुज्जी विधायक भोलाराम साहू हुए गृह प्रवेश कार्यक्रम में शामिल — परिवार को दी शुभकामनाएं, स्व. लाल बहादुर खल्लारे को किया नमन



मेटेपार (गैदाटोला), विकासखण्ड छुरिया।

आज दिनांक 21 अक्टूबर 2025 को ग्राम मेटेपार निवासी श्री ब्रम्हानंद खल्लारे के निवास पर गृह प्रवेश कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर खुज्जी विधानसभा के लोकप्रिय विधायक माननीय श्री भोलाराम साहू मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए।

माननीय विधायक श्री साहू ने नए घर के लिए श्री ब्रम्हानंद खल्लारे एवं उनके परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं व बधाई दी। साथ ही उन्होंने स्वर्गीय श्री लाल बहादुर खल्लारे के बरसा (स्मृति) कार्यक्रम के अवसर पर उनके छायाचित्र पर पुष्प व श्रीफूल अर्पित कर भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की।

कार्यक्रम के दौरान मेटेपार जय माँ लक्ष्मी ग्रुप द्वारा लोककला सांस्कृतिक

कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसकी विधायक साहू ने सराहना करते हुए आयोजकों को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने भारत माता वाहिनी महिला समूह की बहनों से भी भेंट-मुलाकात कर उनके कार्यों की प्रशंसा की।

इस अवसर पर राजू सिन्हा (अध्यक्ष, कार्यकारिणी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी छुरिया), श्रीमती राजकुमारी सिन्हा (पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष, छुरिया), मनोज कुमार सिन्हा (पूर्व सदस्य, अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग), प्रताप घावडे (मंडल अध्यक्ष, उमरवाही कांग्रेस कमेटी), उमेश कंवर (सरपंच प्रतिनिधि, मेटेपार), श्रीमती शारदा कंवर, कृष्णा सलामे, शोभाराम चंद्रवंशी सहित परिवारजन व ग्रामवासी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।

दीपावली में उजाला और आत्मसम्मान का संगम, 30 हजार घरों में पहली बार जलेंगे खुशियों के दीप

रायपुर (संवाददाता)।

इस दीपावली में छत्तीसगढ़ के हजारों परिवारों के घरों में खुशियों का ऐसा उजाला फैलेगा, जो केवल दीपों की रोशनी से नहीं, बल्कि -अपना घर- होने के गर्व और आत्मसम्मान से जगमगाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत रायगढ़ जिले ने उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करते हुए 30 हजार से अधिक आवासों का निर्माण पूर्ण कर लिया है। यह उपलब्धि मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की मंशा और जिला प्रशासन की प्रतिबद्धता से यह सब संभव हो पाया है। प्रदेश के वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी के विशेष प्रयासों से लाभार्थियों के अपना घर पाने का सपना पूरा हुआ है और इस बार की दीवाली में नए घर का आंगन दिए से रोशन होने जा रहा है। रायगढ़ जिले में वित्तीय वर्ष 2024-25 में स्वीकृत आवासों में से इन 30 हजार से अधिक घरों ने निर्माण समय पर पूरा होना न केवल प्रशासनिक दक्षता का उदाहरण है, बल्कि यह

ग्रामीण हितग्राहियों के जीवन में स्थायित्व और सम्मान का नया अध्याय भी जोड़ रहा है। इस बार दीपावली उनके लिए वास्तव में विशेष होगी, क्योंकि इस बार दीये उन घरों में जलेंगे, जिनकी दीवारें खुद उनकी मेहनत, उम्मीदों और सरकारी योजनाओं की संवेदनशीलता की कहानी कह रही हैं।

मिशन मोड में दिखाई दी रायगढ़ की प्रतिबद्धता*

कलेक्टर श्री मयंक चतुर्वेदी के नेतृत्व में रायगढ़ जिले ने प्रधानमंत्री आवास योजना को केवल एक सरकारी कार्यक्रम नहीं, बल्कि एक फ़जन-आंदोलनफ़ का स्वरूप दे दिया। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की टीमों ने गांव-गांव जाकर कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग की, हितग्राहियों की समस्याओं का त्वरित समाधान किया, और हर स्तर पर माइक्रो प्लानिंग से काम को गति दी। जिन क्षेत्रों में निर्माण कार्य धीमा पाया गया, वहां तत्काल समीक्षा बैठकें लेकर कारणों का विश्लेषण किया गया और जिम्मेदार अमले पर सख्त कार्रवाई की गई।

रायपुर : महतारी वंदन योजना से बदली जिंदगी श्यामा बनी आत्मनिर्भरता की पहचान



महतारी वंदन योजना से बदली जिंदगी श्यामा बनी आत्मनिर्भरता की पहचान

रायपुर, संवाददाता

सरकारी योजनाएं तभी असर दिखाती हैं, जब वे सीधे आमजन के जीवन में बदलाव लाएं। छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना ऐसी ही तस्वीर लिख रही है। मुंगेली जिले के ग्राम किरना की श्यामा नेताम इसका उदाहरण है। कभी मजदूरी और सीमित खेती पर आश्रित यह परिवार आज आत्मनिर्भरता की राह पर मजबूती से खड़ा है, वो भी एक छोटे से प्रयास और बड़ी सोच की वजह से। श्यामा को बकरी पालन का अनुभव तो था, मगर पूंजी की कमी बड़ी बाधा थी। इसी

बीच महतारी वंदन योजना के तहत हर महीने मिलने वाले 1,000 रुपये ने उनकी उम्मीद को नई दिशा दी। श्यामा ने राशि खर्च करने के बजाय उसे कुछ महीने तक बचाया और उसी से एक बकरी खरीदी। यहीं से शुरू हुआ बदलाव का सफ़र, रकम भले छोटी थी, लेकिन हौसला बढ़ा।

धीरे-धीरे बकरियों की संख्या बढ़ी और आज श्यामा परिवार की आय में 3000 रुपये प्रति माह जोड़ रही हैं। बच्चों की पढ़ाई हो या रोजमर्रा का खर्च, सब कुछ अब पहले से ज्यादा व्यवस्थित है। सबसे बड़ी बात श्यामा अब खुद को आश्रित नहीं, आत्मनिर्भर कहने लगी हैं। श्यामा नेताम कहती हैं कि 'योजना ने मुझे नया हौसला

दिया। अब मैं अपने पैरों पर खड़ी हूँ। पहले घर चलाना मुश्किल था, लेकिन अब अपने दम पर परिवार संभाल पा रही हूँ। यह योजना सच में महिलाओं के लिए नई शुरुआत है। यह बदलाव यूँ ही नहीं आया। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की पहल छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा संचालित महतारी वंदन योजना का मकसद महिलाओं को केवल सहारा नहीं, आर्थिक स्वतंत्रता देना है। इस योजना की बदौलत श्यामा जैसी हजारों महिलाएं अपनी पहचान और सम्मान की नई कहानी लिख रही हैं। गांव में आज श्यामा प्रेरणा बन चुकी हैं। उनकी मुस्कान बताती है कि छोटे अवसर भी बड़ा भविष्य बना सकते हैं, बस जरूरत है विश्वास, निरंतरता और सही दिशा की।

खास खबर

एसईसीएल में हुई लापरवाही, मजदूर के दोनों हाथ कटे

कोरबा एसईसीएल की लापरवाही की वजह से मजदूर ने खो दिए दोनों हाथ लपरवाही एक बार फिर उजागर हो गई है। बीते दिनों हुई दर्दनाक घटना, जिसमें एक मजदूर के दोनों पैर काटने पड़े, अब टायर फटने की कहानी नहीं रही क् बल्कि सच यह है कि हादसा ब्लास्टिंग में इस्तेमाल होने वाले बुस्टर के फटने से हुआ! जिस तरह से मजदूर का पूरा शरीर झुलस गया था उसे देखते ही इस बात का अंदाजा लगाया जा रहा था कि मजदूर टायर फटने की चपेट में नहीं बल्कि इनके साथ कुछ और ही हादसा हुआ है। सूत्रों के अनुसार, हादसे के समय ट्रक का टायर उस बुस्टर के ऊपर चढ़ गया था जो विस्फोटक सामग्री के तौर पर उपयोग में लाया जाता है। परिणामस्वरूप हुआ धमाका इतना जबरदस्त था कि आसपास की मिट्टी, पथर और कंकर तक हवा में उड़ गए। मगर दीपका प्रबंधन ने इसे टायर फटने की सामान्य दुर्घटना बताकर मामले को दबाने की कोशिश की। स्थानीय सूत्रों का कहना है कि यह घटना महज एक हादसा नहीं, बल्कि गंभीर सुरक्षा लापरवाही का नतीजा है। एसईसीएल प्रबंधन और ठेका कंपनियों द्वारा ब्लास्टिंग के दौरान सुरक्षा मानकों की अनदेखी पहले से की जा रही थी। कई बार यह बात सामने आई है कि ब्लास्टिंग जौन में न तो उचित बैरिकेडिंग की जाती है और न ही वहां कार्यरत कर्मचारियों को हेलमेट, गमबूट और सुरक्षा जैकेट जैसी बुनियादी सुरक्षा सामग्री उपलब्ध कराई जाती है। दीपका खदान क्षेत्र में ब्लास्टिंग के दौरान सुरक्षा मानकों को ताक पर रखा जा रहा है। बावजूद इसके, प्रबंधन ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। नतीजतन आज एक परिवार का चिराग अंधकार में चला गया।अब सवाल उठता है- क्या एसईसीएल प्रबंधन इस गंभीर लापरवाही की जिम्मेदारी लेगा? क्या ब्लास्टिंग में सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा या फिर एक और यार फटने की कहानी रची जाएगी? दीपका खदान में मजदूरों की सुरक्षा आज एक बड़ा सवाल बन चुकी है। यह हादसा सिर्फ एक व्यक्ति की पीड़ा नहीं, बल्कि पूरे तंत्र की सुस्त व्यवस्था पर तीखा प्रहार है।

श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने टी बधाई

कोरबा एवं श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने प्रदेशवासियों को धनतेरस, रूपचैदस, दीपावली, गोवर्धन पूजा एवं भाईदूज पर्व की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने सभी के लिए सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना करी है। कैबिनेट मंत्री श्री देवांगन ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा श्रमिकों एवं उनके परिजनों की बेहतरी के लिए अनेक योजनाएं संचालित की जा रही है। इन योजनाओं के माध्यम से श्रमिकों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के के लिए डीबीटी के जरिए लगातार आर्थिक मदद की जा रही है। कैबिनेट मंत्री ने दीवाली के मौके पर ‘लोकल फॉर वोकल’ को बढ़ावा देने स्थानीय उत्पाद से बने सामग्री का उपयोग करने का आह्वान किया है।

गबन/अनियमितता की गई राषि की वसूली करने के दिए निर्देश

खाद वितरण में किये गये अनियमितता पर समिति प्रबंधक के विरुद्ध एफ आईआर दर्ज कराने तथा सेवा से बर्खास्त करने कलेक्टर ने दिए निर्देश

आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मोरगा के समिति प्रबंधक महेन्द्र शर्मा के विरुद्ध होगी कार्यवाही

कोरबा संवाददाता

आदिम जाति सेवा सहकारी समिति केंद्र मोरगा, विकास खण्ड पोड़ी उपरोड़ा, जिला कोरबा के प्रबंधक के विरुद्ध खरीफ वर्ष 2025-26 में खाद वितरण में गड़बड़ी एवं अनिमियतता करने संबंधी पिकायत प्राप्त होने के पश्चात की गई जांच में पिकायत सही पाये जाने पर कलेक्टर श्री अजीत वर्सत द्वारा समिति प्रबंधक श्री महेन्द्र शर्मा के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने, आरोपी कर्मचारी को सेवा से पृथक करने और गबन की गई राषि आरोपी से वसूलने के निर्देश दिया गया है। कलेक्टर ने अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पोड़ी उपरोड़ा द्वारा दिये गये जांच प्रतिवेदन के आधार पर उक्त कार्यवाही के निर्देश दिये हैं।

इस संबंध में प्राप्त जानकारी के अनुसार

‘मेरा रेशम मेरा अभिमान’ अभियान के तहत कोरबा में जागरूकता कार्यक्रम सह क्रेता-विक्रेता मिलन संपन्न

कोरबा (संवाददाता)।

रेशम तकनीकी सेवा केंद्र, केंद्रीय रेशम बोर्ड, बिलासपुर द्वारा आज «मेरा रेशम मेरा अभिमान» अभियान के अंतर्गत डिंगपुर, कोरबा में एक विशाल जागरूकता कार्यक्रम सह क्रेता-विक्रेता मिलन का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम ने तसर रेशम उद्योग से जुड़े हितधारकों को एक साझा मंच प्रदान किया। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़, ओडिशा एवं झारखंड राज्यों से आए 13 से अधिक तसर व्यापारियों सहित कुल 130 से अधिक प्रतिभागियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य तसर रेशम क्षेत्र में विपणन से जुड़ी समस्याओं पर गहन चर्चा कर उनके समाधान हेतु ठोस रणनीतियाँ तैयार करना था। साथ ही, राज्य रेशम विभाग एवं रेशम तकनीकी सेवा केंद्र द्वारा विकसित ऑनलाइन विपणन प्लेटफॉर्म के बारे में भी प्रतिभागियों को जानकारी प्रदान की गई। इसका लक्ष्य एकल एवं स्व-सहायता समूहों के रीलर, स्पिनर और बुनकर और व्यापारियों के बीच सीधा संबंध स्थापित करना, मार्केटिंग

नेटवर्क को मजबूत करना, राज्य में निर्मित तरह-तरह के धागों को अधिक से अधिक क्रेताओं तक पहुंचाना एवं भविष्य में व्यापार के लिए अधिक विकल्प उपलब्ध करवाना

रहा। कार्यक्रम के पहले सत्र में अशोक कुमार, वैज्ञानिक-बी, रेशम तकनीकी सेवा केंद्र, बिलासपुर द्वारा मुख्य अतिथि डॉ. रजेश बघेल, अपर संचालक, ग्रामोद्योग विभाग (रेशम



हितग्राहियों को नहीं मिली एनटीपीसी की क्षतिपूर्ति राशि

कोरबा संवाददाता।

कोरबा जिले में एनटीपीसी द्वारा राजस्व विभाग को दी गयी क्षतिपूर्ति राशि के भुगतान में हो रही देरी से नाराज ग्रामीणों ने तहसील कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। राखड़ प्रभावित ग्राम धनरास के सैकड़ों ग्रामीण, जिनमें महिलाएं भी शामिल थीं, एसडीएम कार्यालय पहुंच राजस्व विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ग्रामीणों का आरोप है कि एनटीपीसी प्रबंधन ने एक साल की क्षतिपूर्ति राशि दो महीने पहले ही राजस्व विभाग को दे दी थी, लेकिन यह राशि अब तक हितग्राहियों तक नहीं पहुंची है। पहले यह राशि सीधे ग्राम पंचायत के खाते में जमा की जाती थी, लेकिन इस बार यह विभाग के पास अटकी हुई है। ग्रामीणों ने दीपावली से पहले राशि जारी करने की मांग करी है। उनका कहना है कि त्र्यहंजर नजदीक है और मुआवजा न मिलने से ग्राम में आर्थिक संकट की स्थिति बन गई है। ग्रामीणों ने बताया कि एनटीपीसी प्रबंधन द्वारा हर साल क्षतिपूर्ति राशि दी जाती थी। इस बार भुगतान में देरी के कारण उन्हें आंदोलन करना पड़ा हू उन्होंने यह भी बताया कि पहले यह राशि सरपंच और पंच को दी जाती थी, जो इसे प्रभावित लोगों में बांटते थे। अब यह सीधे

प्रभावितों के खाते में जाती है, लेकिन इस बार उन्हें राशि नहीं मिली है। एक अन्य ग्रामीण ने आरोप लगाते हुए बताया कि एनटीपीसी द्वारा डंग की जाने वाली राखड़ से होने वाले प्रदूषण का खामियाजा वे भुगत रहे हैं और बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं। इसी प्रदूषण की क्षतिपूर्ति के रूप में यह राशि दी जाती है, लेकिन इस बार इसका



डेम के पास मिली 3 दिन से लापता युवक की लाश

परिजनों ने जताई हत्या की आशंका, जांच में जुटी पुलिस

रायगढ़, । किरौड़ीमल नगर क्षेत्र स्थित उच्चभिट्टी डेम के पास एक लापता युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई. मृतक जितेंद्र प्लांट में मजदूरी का काम करता था. मौके पर पहुंची पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया और आगे की कार्रवाई में जुट गई है. जानकारी के मुताबिक, युवक पिछले तीन दिनों से लापता था और परिजनों ने उसकी गुमशुगी की रिपोर्ट कोतरा रोड थाने में दर्ज कराई थी. रविवार को डेम के पास



शव मिलने की सूचना पर कोतरा रोड पुलिस मौके पर पहुंची. साथ ही फॉरेंसिक टीम को भी जांच के लिए बुलाया गया है. परिजनों ने युवक की हत्या की आशंका जताई है. फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है. प्रारंभिक जांच में मौत का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है।

फेस्टिवल सीजन: अनहोनी टालने यूनिफॉर्म के साथ सिविल ड्रेस में तैनात पुलिसकर्मों

कोरबा । फेस्टिवल सीजन में कोरबा शहर और इसके उपनगरीय इलाकों में चारों ओर चहल-पहल और रौनक दिखाई दे रही है। धनतेरस से लेकर दीपावली तक चलने वाले पांच दिवसीय पर्व के दौरान बाजारों में जबरदस्त भीड़ उमड़ रही है। ऐसी भीड़भाड़ भरी परिस्थितियों में असामाजिक और शांति तत्वों के सक्रिय होने की संभावना बनी रहती है। इन्हीं संभावित घटनाओं को ध्यान में रखते हुए पुलिस प्रशासन ने विशेष सुरक्षा व्यवस्था की है।शहर और आसपास के प्रमुख बाजार क्षेत्रों, बैंकों, एटीएम और आभूषण की दुकानों के आसपास यूनिफॉर्म के साथ सिविल ड्रेस में पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है, जो भीड़भाड़ वाले स्थानों पर नजर बनाए हुए हैं। पुलिस का उद्देश्य है कि किसी भी अग्रिय



घटना या चोरी-छिपेती जैसी वारदात को पहले ही टाला जा सके। कोरबा नगर, अल्युमिनियम सिटी बालको नगर, कोलफील्ड क्षेत्र कुसमुंडा, में रखते हुए पुलिस प्रशासन ने विशेष सुरक्षा व्यवस्था की है।शहर और आसपास के प्रमुख बाजार क्षेत्रों, बैंकों, एटीएम और आभूषण की दुकानों के आसपास यूनिफॉर्म के साथ सिविल ड्रेस में पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है, जो भीड़भाड़ वाले स्थानों पर नजर बनाए हुए हैं। पुलिस का उद्देश्य है कि किसी भी अग्रिय

पुलिस विभाग ने त्योहारों के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करते हुए सभी संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त फोर्स तैनात की है। वहीं, कई व्यापारी संगठनों ने अपने प्रतिष्ठानों में उच्च गुणवत्ता वाले सीसीटीवी कैमरे लगाकर निगरानी की व्यवस्था की है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि शहर के विभिन्न चेकक्वांट्स पर पुलिसकर्मियों को सख्त निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। सभी को सतर्कता बरतने और संदिग्ध गतिविधियों पर तुरंत कार्रवाई करने के आदेश जारी

किए गए हैं।गौरतलब है कि वर्ष 2020 में सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत कोसाबादी में डीडी इंटरप्राइजेज के संचालक विकास अग्रवाल के निवास पर चोरी की बड़ी वारदात हुई थी। चोरों ने उस समय करीब 30 लाख रुपये की रकम पर हाथ साफ किया था, लेकिन पांच वर्ष बीत जाने के बाद भी यह मामला रहस्य बना हुआ है। पुलिस ने उस समय एक विशेष जांच टीम गठित की थी जिसने घटनास्थल से लेकर घंटाघर चैक तक लगे सैकड़ों सीसीटीवी फुटेज खंगाले थे, लेकिन आरोपी अब तक पुलिस को पकड़ से बाहर हैं। इस घटना के बाद से पुलिस ने त्योहारों के दौरान विशेष रूप से एहतियात बरतना शुरू किया है ताकि ऐसी कोई भी अनहोनी दोबारा न घट सके।

प्रगति वन महिला स्वयं सहायता समूह ने बनाए 7000 रंग-बिरंगे दिए

रामानुजगंज, नगर के वार्ड क्रमांक 7 स्थित तरल, ठोस एवं अपशिष्ट प्रबंधन केंद्र में पिछले 8 वर्षों से महिलाओं के स्वयं सहायता समूह द्वारा डोर टू डोर कचरा कलेक्शन कर लाया जा रहा कचरा खाद बनाने के लिए उपयोग में लाया जा रहा है। इसके साथ ही सूखे कचरे का रीसाइकलिंग कर पर्यावरण हितैषी भी किया जा रहा है। इसी केंद्र में कार्यरत प्रगति वन महिला स्वयं सहायता समूह की महिलाएं पिछले 5 वर्षों से दीपावली के अवसर पर मिट्टी एवं गोबर से बनाए गए रंग-बिरंगे दीयों का निर्माण भी कर रही हैं, जो क्षेत्रवासियों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र बने रहते हैं। इस वर्ष दीपावली से पूर्व समूह की महिलाओं द्वारा तैयार किए गए दीयों की भारी मांग रही। समूह की सचिव सरस्वती ठाकुर ने जानकारी देते हुए बताया कि दीयों का निर्माण गोबर और मिट्टी से किया जाता है, फिर उन्हें सुंदर रंगों से पेंट किया जाता है। प्रत्येक दिया २3 में बंचा जाता है। इस वर्ष समूह द्वारा कुल 7000 दीयों की बिक्री की गई, जिससे महिलाओं को आर्थिक लाभ भी हुआ और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक सशक्त कदम भी सिद्ध हुआ। नगर पालिका अध्यक्ष रमन अग्रवाल ने महिला समूह के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि महिलाएं न केवल स्वच्छता अभियान के तहत घर-घर जाकर कचरा संग्रहण कर रही हैं, बल्कि खाली समय का सदुपयोग कर स्वरोजगार को बढ़ावा भी दे रही हैं। दिया निर्माण जैसी गतिविधियों से महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त हो रही हैं और समाज को स्वच्छता व सांस्कृतिक विरासत से जोड़ने का कार्य कर रही हैं।

